RNI Reference No. 1328500

01-15 जनवरी, 2019

2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 12/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

नव वर्ष की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा में आईआईआरडी की बड़ी पहल

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ हुई साझेदारी

राष्ट्रीय स्तर पर मिली कॉर्पोरेट सदस्यता

प्रदेश और देश में मिशन रीव के तहत दी जाएगी सेवाएं

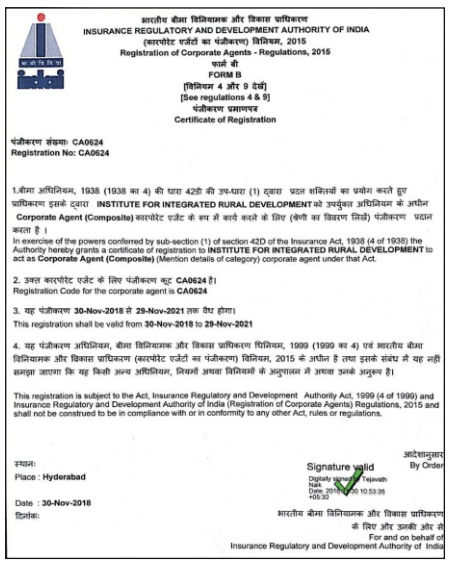

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
Registration of Corporate Agents - Regulations, 2015
फार्म बी
FORM B
[विनियम 4 और 9 देखें]
[See regulations 4 & 9]
पंजीकरण प्रमाणपत्र
Certificate of Registration

पंजीकरण संख्या: CA0624
Registration No: CA0624

1.बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा **INSTITUTE FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT** को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन **Corporate Agent (Composite)** कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए (श्रेणी का विवरण लिखें) पंजीकरण प्रदान करता है ।
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to **INSTITUTE FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT** to act as **Corporate Agent (Composite)** (Mention details of category) corporate agent under that Act.

2. उक्त कारपोरेट एजेंट के लिए पंजीकरण कूट **CA0624** है।
Registration Code for the corporate agent is **CA0624**

3. यह पंजीकरण **30-Nov-2018** से **29-Nov-2021** तक वैध होगा।
This registration shall be valid from **30-Nov-2018** to **29-Nov-2021**

4. यह पंजीकरण अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

This registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थान: Place : Hyderabad
Date : 30-Nov-2018
दिनांक:

आदेशानुसार
By Order
Signature valid
Digitally signed by Tejswath Nath
Date: 2018.12.10 10:53:35 +05:30
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

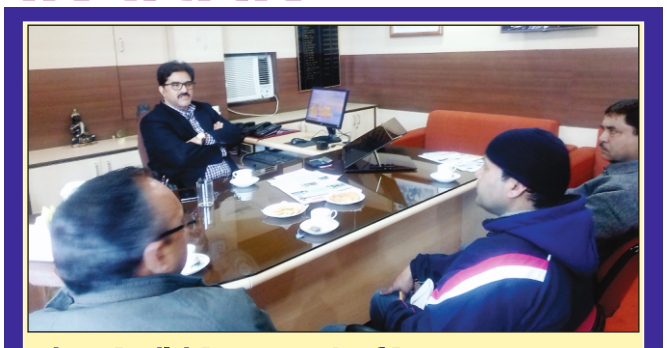

प्रदेशवासियों के लिए आशा की नई किरण : अरुण राजदान

भारतीय जीवन बीमा निगम के सीनियर डिवीजनल मैनेजर, हिमाचल प्रदेश अरुण राजदान आईइआईआरडी के साथ हुए इस समझौते को प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर के रुप में देखते हैं ।

द रीव टाइम्स सहायक संपादक हेम राज चौहान के साथ बातचीत में अरुण राजदान ने बताया कि आईआईआरडी को कॉर्पोरेट सदस्यता मिलने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा क्षेत्र में नई उंचाईयों को छूऐगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आईआईआरडी के सराहनीय पहल मिशन रीव की पकड़ गांव–गांव में होने के कारण इस दिशा में वांछित सफलता की आशा की जा रही है। मिशन रीव के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के विषय पर पुछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक खण्ड स्तर पर एलआईसी प्रशिक्षण को आयोजित करेगी तथा शिमला में भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिये जाने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 0 से 100 तक के आयु वर्ग के लिए प्लान है तथा प्रत्येक तरह के प्लान के साथ आईआईआरडी अपनी सेवाऐं दे सकती है।

अरुण राजदान ने कहा कि एलआईसी सिर्फ नाम नहीं है बल्कि बीमा क्षेत्र में एक ब्रांड है और भारत की सबसे भरोसेमंद भी। इसलिए प्रदेश में आईआईआरडी के साथ सहयोग करके लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त किया जाएगा। संस्था को 01 कोड शाखा के साथ जोड़ा गया है जिससे अब संस्था प्रदेश के बाहर से भी अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं। उन्होंने संस्था को बेहतर परिणाम एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने व लोगों को आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत के लिए बधाई दी है।

द रीव टाइम्स (हेमराज चौहान)

आईआईआरडी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ साझेदारी कर राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट सदस्यता प्राप्त कर ली है। ये साझेदारी आईआरडीए के नियमों पर खरा उतरने के बाद हुई जिसके तहत अब संस्था विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे हिमाचल में तो लोगों को विभिन्न प्रकार का बीमा करवाया ही जाएगा साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्यों में इसका विस्तार किया जाएगा। यानि संस्था द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में भी अब किसी भी प्रकार के बीमा करवाने में आईआईआरडी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गौरतलब है कि आईआईआरडी के जनोपयोगी प्रयास मिशन रीव ने हिमाचल प्रदेश के गांवों को विभिन्न सुविधाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया है। लोगों को घर–द्वार पर सुविधाओं की सरल एवं गुणात्मक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रीव के कार्यकर्ता सेवाऐं दे रहे हैं। इसी के तहत एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी संस्था ने मिशन रीव के माध्यम से लोगों को बीमा के दायरे में लाने का निर्णय लिया। इसके लिए भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समझौता कर अब यह राह भी आसान हो गई है।

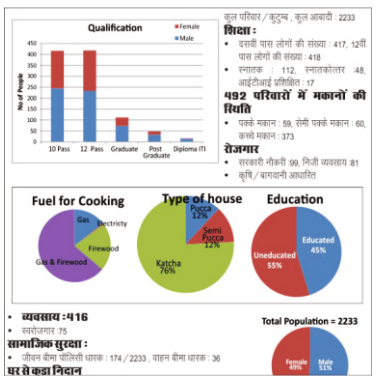

आईआईआरडी ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया था जिसमें हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए थे । इसे द रीव टाइम्स में भी प्रकाशित किया गया था । इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं । अनहोनी या आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर आर्थिक सुरक्षा के नाम पर पीछे छूट गए परिवार के लिए शेष नहीं बचता है। ऐसी भी स्थितियां बनी है जिसमें परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे और अमूमन ऐसा बहुतों के साथ होता है, सर्वेक्षण में यह भी सामने आया था।

इसी लक्ष्य और सेवा में मिशन रीव भविष्य की राह आसान करेगा। अनहोनी होने की स्थिति में अब इतना तो सुनिश्चित किया जाएगा ही कि परिवार को पीछे बहुत मुश्किलों का सामना न करना पड़े और आर्थिक सहायता से परिवार को सुरक्षा चक्र में रखा जा सके।

प्रमाणीकरण के बाद आगे क्या

आईआरडीए से प्रमाणीकरण एवं एलआईसी से साझेदारी के बाद प्रदेश के गांव–गांव में मिशन रीव के मज़बूत नेटवर्क के साथ लोगों को जीवन बीमा एवं अन्य प्रकार के समस्त आवश्यक बीमा हेतु जागरुक किया जाएगा तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाऐगा। यह सुनिश्चित करने की मिशन रीव जिम्मेवारी लेगा कि कोई भी परिवार इस दायरे से बाहर न रहे। आकस्मिक दुर्घटना अथवा परिवार के मुखिया के साथ कोई अकस्मात घटना घटित हो जाने पर अंतिम समय में पड़ने वाले आर्थिक संकट के साथ–साथ पीछे छूट गए परिवार को आर्थिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा के अतिरिक्त सभी प्रकार के बीमा के लिए अब घर पर ही लोगों को सुविधाओं की उपलब्धता होगी। मिशन रीव इस के लिए प्रारंभिक योजना का प्रारुप तैयार कर इस पर कार्य आरंभ कर चुका है। यह सारी प्रक्रिया बेहतर ऑनलाइन एवं ऑफलाईन प्रारुप के सहयोग से और अधिक सुगम्य बनाई जाऐगी। बच्चों, जननी, युवा, बुजुर्ग यानि हर वर्ग के लिए बीमा के क्षेत्र में संबन्धित करने का लक्ष्य है। साथ ही वाहनों, संपत्ति, मकान, कार्यालय एवं अन्य समस्त प्रकार की बीमा को भी ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर ही सुगम्य बनाया जाएगा।

पूर्व में भी ग्रामीण त्रासदी की व्यथा संपादकीय लेख में हुई थी उजागर

सामाजिक सुरक्षा : ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चुनौती

आईआईआरडी का सर्वेक्षण दिखाता है गांव की असल तस्वीर

विकास की दौड़ में बहुत कुछ पीछे छूट गया है। ऐसा लगता है कि अब शायद शताब्दी भारत की शताब्दी होने से कोई रोक नहीं सकता है। हम ज्ञान से विज्ञान तक के क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं और दुनिया हमारे देश को सलाम कर रही है। पर क्या इस विकास का मूल और आधार हमारे गांव और ग्रामीण भी इसी विकास की गति के साथ इस दौड़ में अग्रसर है, इसमें संदेह है । ऐसा नहीं कि सब संतोषीय के बाद विकास हुआ नहीं या कम हुआ है किंतु विकास के मायने गांव में आकर बदल जाते हैं। रोजमर्रा की जिन्दगी आसान हुई है किंतु सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और जिलों के विकास का हजारों मील दूर गांव में शुरुआत... शब्द नहीं ही पाया। कुछ समय पहले आईआईआरडी द्वारा शिमला जिले के दूरदराज गांव शोली में एक महत्वपूर्ण विस्तृत सर्वेक्षण करवाया गया। इस सर्वेक्षण में अनेक मानकों पर गांव की सामाजिक स्थिति का आकलन जब हुआ तो ये विकास की दौड़ वहां धीमी पड़ती ही नजर आई। टीन-टप्पर, कंकरीट का जंगल ही विकास नहीं होता, विकास हमारी सामाजिक सुरक्षा, ज्ञान, शिक्षा के अलावा अपने कौशल विकास का भी आधार होता है। संस्था ने इस सर्वेक्षण की प्रत्येक मानकों पर बारीकी से करवाया तथा इसमें प्राप्त आंकड़ों से कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई।

सर्वेक्षण क्षेत्र : शिमला जिले के ननखड़ी विकास खण्ड का गांव शोली

इससे वंचित है। कई लोगों को तो पता भी नहीं कि जीवन बीमा है क्या?
अभी एक पूर्व में ही द रीव टाइम्स के एक अंक में प्रधान संपादक डॉ॰ एल सी शर्मा ने शोली गांव के आस–पास के क्षेत्र की दो उदाहरण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा की पोल खोली थी। दो परिवारों को किस प्रकार विपदा ने घेरा जब उनके घरों के मुखिया की स्थिति में एक दुर्घटना ने क्षीण किया। उनके अंतिम संस्कार तक के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी। किया ये कि अब बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और भविष्य की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया। यह तभी हुआ क्योंकि उन दोनों घरों के मुखिया और परिवार का कोई भी जीवन बीमा नहीं था। यदि होता तो भविष्य के लिए कुछ राहत मिलती साथ ही इस संकट के समय में आर्थिक सहायता व भरोसा भी।

अनुशंसा :
इस दौर में भी यदि सामाजिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित नहीं करवा पर रहे हैं तो इसे हमारी व्यवस्था और लापरी की विडम्बना कहा जाऐगा। आवश्यकता है लोगों को जागरुक करने और अधिक से अधिक जोड़ने की ताकि प्रत्येक व्यक्ति

प्रधान संपादक द रीव टाइम्स डॉ0 एल सी शर्मा के एक पूर्व में प्रकाशित संपादकीय लेख में ग्रामीण परिवेश में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की त्रासदी सामने लाई गई थी। जिसमें दो परिवारों के मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाने पर परिवार पर घोर आर्थिक संकट आ गया और दोनों ही परिवार किसी भी प्रकार के सुरक्षा बीमा में पंजीकृत नहीं थे।

मिशन रीव एलआईसी के सहयोग से देगा प्रशिक्षण

इस बड़े अभियान के लिए मिशन रीव के पास प्रदेश भर में कर्मियों का एक मज़बूत नेटवर्क हैं जो बीमा के क्षेत्र में अपनी सेवाऐं देगा। इसके लिए मिशन रीव भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से इन चयनित रीव कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

मूलतः यह प्रशिक्षण प्रदेश के विभिन्न ज़िलों एवं खण्ड स्तर में भिन्न–भिन्न स्थानों पर आयोजित होगा। उसके बाद इसे ग्रामीण स्तर पर भी सहयोगी टीम को दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ही प्रारुपों में आयोजित होगा। मिशन रीव इसका निःशुल्क आयोजन करेगा। प्रशिक्षण के बाद मिशन रीव के संबन्धित प्रभाग के माध्यम से इन सेवाओं का विस्तार गांव–गांव में होगा तथा प्रदेश के लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में एलआईसी की ओर से कुछ अधिकारियों का विशेष योगदान रहा जिनमें मैनेजर सुनील दत्त शर्मा एवं डिप्टी मैनेजर संजीव करोल शामिल हैं ।

मिशन रीव... सफलता भरा एक वर्ष...

नववर्ष के आगमन पर जहां हम अपने जीवन में कुछ नए लक्ष्य तय करते हैं वहीं बीते वर्ष के अनुभवों और उपलब्धियों का भी आकलन करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए हम भी वर्ष 2018 में आईआईआरडी मिशन रीव की विभिन्न गतिविधियों और कुछ यादगार लम्हों को 'द रीव टाइम्स' के इस अंक में आप से साझा कर रहे हैं। साथ ही साझा कर रहे हैं नव वर्ष पर अपने सदस्यों और गांव को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हमारे संकल्प।

26 फरवरी 2018– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर द्वारा मिशन रीव की विभिन्न सेवाओं का आगाज

मिशन रीव की सफलता के इतिहास में फरवरी 2018 को एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर ने आईआईआरडी शिमला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मिशन रीव की विभिन्न सेवाओं का लोकापर्ण किया। उन्होंने उस दौरान कहा कि मिशन रीव गांव के विकास का बहुत बड़ा मिशन साबित होगा।

ब्लॉक स्तर पर खुले कार्यालय

मई 2018 – प्रदेश के गांव गांव तक मिशन रीव की सेवाओं को सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए विभिन्न ब्लॉक कार्यालयों की स्थापना की गई जहां से मिशन रीव की सेवाओं से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

15 जुलाई 2018 – द रीव टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित

15 जुलाई को मिशन रीव के तहत गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया गया। आज प्रदेश की लगभग हर पंचायत तक द रीव टाइम्स पहुंच रहा है।

16 जुलाई 2018– एसीएस स्वास्थ्य द्वारा 5 जनऔषधि केंद्रों का उद्घाटन–

16 जुलाई का दिन आईआईआरडी मिशन रीव के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी काफी अहम रहा। इस दिन तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आईआईआरडी मुख्यालय शिमला से पांच जनऔषधि केंद्रों का उद्घाटन किया और केंद्र संचालकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान शिमला, मंडी के छतरी, बंगरोटू, कांगड़ा के नूरपुर व पालमपुर और हमीरपुर के जाहू में जनऔषधि केंद्रों का उद्घाटन हुआ। इसके बाद कुल्लू, चंबा समेत अन्य जिलों में जनऔषधि केंद्र खोलने का सिलसिला लगातार जारी है।

अगस्त 2018 – उत्कृष्ट एनजीओ ऑफ सीएसआर टाइम्स पुरस्कार

आईआईआरडी को उत्कृष्ट एनजीओ ऑफ सीएसआर टाइम्स का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार झारखंड में आईआईआरडी की ओर से जनजातीय महिलाओं के उत्थान के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट रूपांतरण के बेतरीन कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया।

अगस्त 2018– ऑयस्टर मशरूम पायलट प्रोजेक्ट

ग्रामीणों की आर्थिकी सुधार के लिए मिशन रीव के तहत लोगों को ऑयस्टर मशरूम उगाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए अगस्त 2018 में शिमला मुख्यालय में पायलट आधार ऑयस्टर मशरूम का प्लांट लगाया गया जो पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद जिला मंडी में भी यह प्रयोग सफल रहा।

अगस्त 2018– विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद का प्रशिक्षण शुरु

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में मिशन रीव के तहत अहम योगदान दिया जा रहा है। गांव के लोगों को जैविक खेती से जोड़ने और प्रदेश के खेतों को रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए मिशन रीव की ओर से गांव के लोगों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

5 सितंबर 2018 – जिंदगी जियें–नशा नहीं अभियान का आगाज

5 सितंबर को शिमला से जिंदगी जियें नशे को नहीं–अभियान का शानदार आगाज किया गया। एक माह तक चले इस अभियान के दौरान प्रदेश के 200 से अधिक स्कूलों में विभन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आम लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गईं, जैड कार्ड बांटे गए। प्रदेश के करीब 10 हजार लोग इस अभियान का हिस्सा रहे जबकि स्कूलों में आयोजित भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता में 550 छात्र–छात्राओं ने विजेता के तौर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

सितंबर 2018–मृदा परीक्षण सुविधा का शुभारम्भ

मिशन रीव के तहत गांव के किसानों की खेती को और बेहतर बनाने के लिए जैविक खाद के बाद मृदा परीक्षण की सुविधा को भी सितं बर 2018 में मिशन रीव की सेवाओं में शामिल किया गया। हाल ही में उपरी शिमला में विभिन्न स्थानों पर मृदा परीक्षण शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक किसानों ने मृदा जांच के लिए अपने खेतों की मिट्टी दी और इन किसानों को जांच के बाद रिपोर्ट भी दी गई।

30 सितंबर 2018– मिशन रीव की पहली वर्षगांठ पर रीव संस्करण दो का आगाज

30 सितंबर के दिन ही वर्ष 2017 में केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं पंचायती राज परषोत्तम रूपाला ने आईआईआरडी शिमला से मिशन रीव का आगाज किया था। इस तरह 30 सितंबर 2018 को मिशन रीव की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर रीव संस्करण दो की शुरूआत भी आईआईआडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एल.सी. शर्मा द्वारा की गई। इस संस्करण में गांव के लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए रीव संस्करण–दो में दस अलग अलग सेवा डिविजन शामिल किए गए।

2 अक्तूबर 2018– शिक्षा मंत्री ने जिंदगी जियें– नशे को नहीं अभियान के विजेताओं को नवाजा

2 अक्तूबर 2018 को गांधी जयंती के अवसर पर आईआईआरडी के जिदंगी जियें– नशे को नहीं अभियान के समापन अवसर पर आईआईआरडी कार्यालय में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश शिक्ष मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अभियान के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर शिमला नगर निगम की महापौर कुसम सदरेट भी बतौर विशेष अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

अक्तूबर 2018–कनार्टक में ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास

अक्तूबर 2018 में आईआईआरडी की ओर एक और उपलब्धि हासिल की गई। अक्तूबर 2018 को कनार्टक के धारवाड़ में बहुद्देशिय इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया गया और अब कार्य प्रगति पर है।

अक्तूबर 2018– आईआईआरडी में खुला रीव क्लीनिक

आईआईआरडी के मिशन रीव के तहत शिमला मुख्यालय में रीव क्लीनिक की शुभारंभ भी अक्तूबर 2018 में किया गया। यह क्लीनिक अत्याधुनिक टेस्ट सुविधाओं से लैस है और यहां पर ईसीजी कराने की सुविधा भी मरीजों को मिल रही है।

नवंबर 2018– आईआईआरडी को एनएसडीसी से मिला पार्टनरशिप सर्टीफिकेट–

नवंबर 2018 – हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से आईआईआरडी को हिमाचल में पांच केंद्र चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 300 अभ्यर्थियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

दिसंबर 2018 – एलआईसी ने आईआईआरडी को बनाया कोओपरेटिव एजेंट

एलआईसी की ओर से नवंबर 2018 में आईआईआरडी को बतौर कोओपरेटिव एजेंट सहमति प्रदान की गई। एलआईसी की विभिन्न योजनाओं को गांव के लोगों को पहुंचाने के लिए आईआईआरडी अधिकृत एजेंट के तौर पर कार्य करेगा।

सितंबर 2018– चंबा पहला कैशलैस जिला

मिशन रीव की ओर से चंबा में एक बेहतरीन पहल की जा रही है। बीते सितंबर मे मिशन रीव के तहत सभी प्रतिनिधियों को पीओएस मशीनें दी गई थी। इन मशीनों को देने का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को सेवा प्राप्ती के लिए कैश रखने की परेशानी से मुक्त करना है। चंबा की तर्ज पर मिशन रीव के तहत अन्य जिलों में भी जल्द ही पीओएस मशीनों से ही सभी भुगतान किया जाएगा और सभी मिशन प्रतिनिधियों को पीओएस मशीने दी जाएंगी। चंबा के जिला समन्वयक राकेश शर्मा का कहना है कि मिशन रीव चंबा को कैशलैस करने की ओर से तेजी से अग्रसर है। अधिकतर प्रतिनिधियों को पीओएस मशीनें दी जा चुकी है और जहां किन्हीं कारणों से मशीनें नहीं पहुंच पाई वहां भी जल्द ही पीओएस से भुतगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

मिशन रीव नव वर्ष आगमन 2019

नव वर्ष यानी 2019 में मिशन रीव संस्करण–दो की सेवाओं को गांव तक पहुंचाना
10 प्रभागों के आधार पर लोगों की आवश्यक्ताओं का आकलन करना
आयु वर्ग और वर्ग विशेष के आधार पर सेवाएं प्रदान कराना
10 प्रभागों के बेहतर संचालन के लिए पंचायत, ब्लॉक , जिला और राज्य स्तर पर मिशन अधिकारियों की नियुक्ति करना
पंचायत, ब्लॉक , जिला और राज्य स्तर पर सलाहाकार बोर्ड की स्थापना
प्रदेश के युवाओं को एचपी पीएमकेवाई और एनएसडीसी के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कौशल विकास का प्रशिक्षण देना
मिशन रीव के तहत प्रदेश के 10 हजार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करना
रीव प्रतिनिधियों को टैब देना ताकि मिशन की सेवाओं को समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके
सभी जिलों में किसानों को गांव में ही मृदा जांच की सुविधा उपलब्ध कराना
हिमाचल को 100 फीसदी जैविक राज्य बनाने के लिए सभी किसानों को जैविक खाद का प्रशिक्षण देना
किसानों द्वारा तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाने में सहयोग करने के लिए नेटवर्क तैयार करना
सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सहयोग करना

'प्रसन्नता का विज्ञान' विषय पर कार्यशाला

एसजेवीएनएल के कर्मचारियों के लिए एनएलपी प्रशिक्षण

आईआईआरडी ने आयोजित किया प्रशिक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

'सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड की महिला कर्मचारियों के लिए आईआईआरडी द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया । इंसान का दिमाग किस प्रकार कार्य करता है तथा इसका अधिकतम सकारात्मक उपयोग कैसे हो.....इस पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। महिला सशक्तिकरण विषय पर भी प्रशिक्षण दिया गया। आईआईआरडी एवं फ्लायरज ग्रुप प्राइवेट लि. की ओर से प्रबन्ध निदेशक डॉ0 एल.सी. शमा, निदेशक सुषमा शर्मा और मिशन रीव हैड आन्नद नायर ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। डॉ. एल. सी. शर्मा ने महिला सशक्तिकरण, क्रोध प्रबन्धन, करियर, सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच का प्रभाव आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया।

प्रशिक्षक मनोज शर्मा ने चेतन और अवचेतन मन की प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आदि विषयों पर भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण रहा। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सतलुज जल विद्युत निगम लि. की ओर से 24 महिलाओं ने भाग लिया।

कृषि एवं मृदा जांच विशेषज्ञ ने किया जुब्बल का दौरा

किसानों से की चर्चा, किया समस्याओं का समाधान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिमला के बागवान अब मृदा जांच के माध्यम से अपनी बागवानी को और अधिक बेहतर कर रहे हैं। मृदा जांच की सुविधा यदि खेतों और घर–द्वार पर ही उपलब्ध हो तो बागवान इस अवसर को गवांना भी नहीं चाहते। रीव मृदा जांच की सुविधा का लाभ जुब्बल–कोटखाई के साथ–साथ रोहड़ू और अन्य क्षेत्रों के किसान–बागवान भरपूर ले रहे हैं। इसी के तहत जुब्बल के विभिन्न गांवों में किसान एवं बागवानों की मृदा जांच की गई थी जिसके परिणाम भी किसान–बागवानों को दे दिए गए थे। इसके बाद किसानों की कुछ समस्याऐं और जिज्ञासाऐं भी थी जिसके लिए मिशन रीव के कृषि, बागवानी एवं मृदा विशेषज्ञ सेवानिवृत डॉ. एस पी भारद्वाज ने संबन्धित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से बात की। किसानों ने अपनी कृषि एवं मृदा संबन्धि समस्याओं को विशेषज्ञ एवं टीम के सामने रखी।

दरअसल, मृदा जांच रिपोर्ट के बाद बागवानों ने आवश्यक पोषक तत्वों को समझने एवं मृदा में कमियों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह की मांग की थी। मिशन रीव भी मृदा जांच के बाद रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किसानों को आवश्यक जानकारी एवं उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए सेवाऐं दे रहा है। किसानों को मृदा में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और रीव जैविक खाद आदि की किस मिश्रण के साथ आवश्यकता है...यह सभी कुछ किसानों को रीव विशेषज्ञ गांव में जाकर जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान में भी जुब्बल के किसान एवं बागवानों को उनके सैंपल के जांच की वैज्ञानिक जानकारी के साथ–साथ पौधों एवं फसलों के लिए मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों का समावेश करना है, इसकी जानकारी दी गई।

गांव मिहाणा और गांव धार के बागवानों से चर्चा की गई। इन गांवों के बागवानों से विशेषज्ञ द्वारा परामर्श लिया गया। साथ ही 47 नए सैंपल भी मृदा जांच हेतु संग्रहित किए गए। इस अभियान में प्रबन्ध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा, निदेशक सुषमा शर्मा, मिशन हैड आन्नद नायर,मुकुल सक्सेना, सेब विशेषज्ञ एस पी भारद्वाज शामिल हुए ।

ननखड़ी में किसान गुज्जरों ने तैयार की रीव जैविक खाद

किन्नौर को भेजी रीव जैविक खाद की खेप

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में मिशन रीव के तहत जैविक खेती के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है । इसी के तहत अधिक से अधिक रीव जैविक खाद के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है । ननखड़ी में गुज्जर किसानों ने रीव जैविक खाद तैयार की है जिसकी पहली खेप किन्नौर के बागवानों के लिए भेजी गई है । गौरतलब है कि किन्नौर में रीव जैविक खाद की धीरे–धीरे मांग जोर पकड़ती जा रही है । बागवानों के लिए मृदा जांच की सुविधा भी अब घर पर ही मिल रही है और इस प्रकार आवश्यकतानुसार रीव जैविक खाद को तैयार किया जा रहा है ।

ननखड़ी में किसान रीव जैविक खाद तैयार कर न केवल अपने खेतों में इसका उपयोग कर रहे हैं बल्कि इसे अन्य स्थानों के लिए भी भेजा जा रहा है ।

महापौर ने किया इंजनघर संजौली का दौरा

विवादित संपर्क सड़क निर्माण पर सुनी लोगों की समस्याऐं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पिछले अंक में प्रकाशित इंजनघर के समीप स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद प्रस्तावित सड़क की ख़बर पर नगर निगम शिमला महापौर कुसुम सदरेट ने मौका का दौरा किया तथा लोगों से बात की। इस सड़क के बनने पर महापौर ने भी कहा कि यह देखने का विषय है कि क्या यहां सड़क बन भी सकती है अथवा नहीं ? वयोवृद्ध आर के गुप्ता ने पहले ही इस सड़क के निर्माण पर आपत्ति जताई है तथा समय–समय पर प्रशासन, नगर निगम शिमला को लिखित रुप से इसे बंद करने की गुहार लगाई है। आर के गुप्ता ने कहा कि उनका मकान 150 वर्ष पुराना है। यहां इतनी चढ़ाई है कि गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती। और यदि यह सड़क बनाई भी जाती है तो यहां दुर्घटना की पूरी संभावनाऐं रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह रास्ता आम रास्ता है जिससे बच्चे, बुजुर्ग सभी चलते हैं। इससे सड़क का निर्माण हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल कर नियमों के खिलाफ इस सड़क का निर्माण करवा रहे हैं जिससे उनके मकानों को भी ख़तरा हो चुका है। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए ही इस प्रकार की मनमानी चल रही है। महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि नियमों के खिलाफ इस सड़क को स्वीकृति नहीं दी जा सकती और इस विषय पर वो स्वयं हस्तक्षेप कर मामले को देखेगीं। क्षेत्रवासियों ने हस्ताक्षर सहित नगर निगम आयुक्त पंकज राय और महापौर को शिकायत पत्र सौंपा है।

युवा फंसता जा रहा है नशे के जंजाल में शिमला में बढ़ रही है घटनाऐं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजधानी शिमला ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला में नशे के प्रति युवाओं का रुझान शोचनीय विषय बन गया है । आए दिन पुलिस ज़िला में नशे में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है । हैरान करने वाली बात ये है कि इसमें अधिक तादात युवाओं की है । ये युवा विभिन्न कारणों से धीरे–धीरे नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं और फिर शुरु होता है अपराध करने का सिलसिला।

इतना ही नहीं युवाओं में बिना ज़्यादा मेहनत कर रातोरात मालोमाल होने और पैसा कमाने की ग़लत प्रवृति भी उन्हें नशे के दलदल में धकेल रही है। ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन शिमला ज़िला में इस प्रकार की घटनाऐं सामने न आती हो। ये बेहद चौंकाने वाले तथ्य है क्योंकि युवाओं में बढ़ती नशे की आदत कहीं न कहीं समाज को भी खोखला करती जा रही है। सबसे अधिक मामले जानलेवा चिट्टे की खेप के हैं जिसमें युवा स्वयं को बर्बाद कर चुका है ।

इससे पूर्व आईआईआरडी ने भी प्रदेश भर में नशा मुक्त हिमाचल के अंतर्गत 'ज़िंदगी जियें–नशा नहीं' अभियान से अधिकतर विद्यालयों एवं युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों में जागरुकता चलाई थी। इस अभियान का स्वयं प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने नेतृत्व कर नशे के प्रति प्रदेश को जगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जो कि अभी भी जारी है।

इसका दूसरा चरण प्रगति पर है और यही प्रयास है कि नशे में लिप्त युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए परामर्श केन्द्र और अन्य प्रयासों को अमल में लाया जाए।

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का 12वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । आशा करता हूं कि पिछला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। 'द रीव टाइम्स' लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का क्रमबद्ध समावेश किया जा सके ।

आसान हुआ गांव का जीवन, रोजमर्रा का सामान भी घर पर

टीम रीव, ऊना

मिशन रीव के तहत लोगों को स्वास्थ्य और कृषि संबंधि सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी अपने स्तर पर उपलब्ध करा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को विभिन्न तरह के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रानिक सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके अलावा क्रॉकरी व अन्य सामान भी लोगों को उनके घरों पर बाजार से बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं से लोगों में भी काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें छोटी – छोटी चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ रहा था लेकिन अब मिशन रीव के तहत उन्हें हर तरह की सुविधाएं घर पर ही मिल रही है।

इससे उनके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है। ऊना के गुगलैहड़ पंचायत में मिशन रीव लोगों के जीवन का सहयोगी बन चुका है। यहां पर सहायक ब्लॉक संयोजक साहिल उपमन्यु पंचायत के लोगों के जीवन को मिशन रीव के माध्यम से आसान बनाने में लगे हैं। इस पंचायत में ऐसे अनेक उदाहरण है जब लोगों ने मिशन रीव के सामने अपनी मांग रखी और मिशन रीव प्रतिनिधियों द्वारा उसे बिना समय गवांए पूरा कर लिया गया।

लोअर भांजल क्षेत्र में लोगों ने रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिशन रीव के तहत घर पर ही प्राप्त किया। लोगों ने गीजर लगवाने, लाइसेंस बनाने जैसे कई कार्य मिशन रीव से करवाए।

गगरेट ब्लॉक में मावा कोहलान के हरदयाल सिंह व ज्ञान चंद, मदवारा के हरदयाल सिंह ने मिशन रीव की सेवाओं का लाभ लेते हुए जरूरत का सामान घर पर ही प्राप्त किया।

आत्मनिर्भर हो रहे गांव के युवा

अपनी ही पंचायत में काम करने का मिला मौका

टीम रीव, सिरमौर

सिरमौर में मिशन रीव के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर सेवाए प्रदान की जा रही है। सेवाओं के साथ ही मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के सबसे बड़े मिशन की ओर अग्रसर है।

ज़िले के अभी तक करीब सैकड़ों ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है तथा वे सभी ग्रामीण स्तर, खण्ड स्तर एवं ज़िला स्तर पर अपनी सेवाऐं प्रदान कर रहे हैं। अभी भी यह प्रक्रिया जारी है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ज़िला में विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। इससे किसानों में रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद बनाने व उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पंचायतों में फेसिलिटेटर पंचायत से संपर्क कर गांव–गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण भी कर रहे हैं। लोगों की मांग पर कम कीमत में फूलों का बीज, मटर तथा मक्की का बीज लोगों को उनके घर पर ही प्रदान किया गया। ऑनलाइन सेवाओं के बारे में आम ग्रामीणों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है तथा किस प्रकार ऑनलाइन बिजली के बिल, टेलिफोन एवं अन्य बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है ।

ऑनलाइन सिस्टम भी जान रहे ग्रामीण पंचायत में ही रोजगार से खुशी

मिशन रीव से गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। लोगों को उनके घरों में ही टेस्ट सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई बाजार से दवाईयां लाना चाहता है तो वह भी मिशन रीव के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सुविधा से मिलने से ग्रामीण काफी खुश है।

ऊना में किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण

टीम रीव, ऊना

मिशन रीव के तहत प्रदेश के हर जिले में ग्रामीणों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऊना में भी जैविक खाद लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने का जरिया बनता जा रहा है। गगरेट के गुगलैहड़ में पिछले दो सप्ताह के भीतर करीब 20 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए जिसमें 50 से अधिक लोगों को जैविक खाद तैयार करने की विधि बताई गई।

उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव –गांव जाकर किसानों और बागवानों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया गया है। संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन आईआईआरडी ने इसे आसान बना दिया है। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

- **जैविक खाद के लाभ**
- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
- सिचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।

मिट्टी की दृष्टि से लाभ

- जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती हैं।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।

पर्यावरण की दृष्टि से

- भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है।
- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण मे कमी आती है।
- कचरे का उपयोग, खाद बनाने में, होने से बीमारियों में कमी आती है।
- फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि
- अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना।

मिशन रीव के सहयोग से शुरू हुआ सिलाई सेंटर

घर के पास ही महिलाएं ले रही सिलाई का प्रशिक्षण

टीम रीव, सोलन

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत कई तरह के प्रयास किए जा रहा है। इसमें महिलाओं को कौशल विकास के लिए भी मिशन रीव के तहत सहयोग किया जा रहा है।

स्थानीय महिलाओं की मांग पर सोलन ब्लॉक के नेरीकलां पंचायत में सिलाई सेंटर मिशन रीव के सहयोग से खोला गया। गांव में महिलाओं से उनकी जरूरतों के बारे में जानने के लिए उनसे बात की गई थी। महिलाओं ने मांग रखी कि गांव की कई महिलाएं सिलाई सीखने की इच्छुक हैं लेकिन आसपास कोई सिलाई सेंटर न होने के कारण महिलाओं की यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। महिलाओं की इसी मांग पर रीव ब्लॉक कार्यालय में मिशन रीव के तहत सिलाई केंद्र के लिए जगह उपलब्ध कराई गई।

इस सिलाई सेंटर का उद्घाटन विशेष तौर पर स्थानीय पंचायत प्रधान ने किया था। इस मौके पर उन्होंने सिलाई सेंटर के लिए मशीन भी दी।

तारा, मीना, ममता, फूलमती व अन्य महिलाओं ने बताया कि सिलाई सेंटर खुलने से गांव की महिलाओं में काफी खुशी है क्योंकि अब सिलाई सीखना आसान हो गया। सिलाई सेंटर पंचायत में ही खुलने से वह घर का कामकाज करने के साथ ही आसानी से सिलाई का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर काफी मददगार साबित हो रहा है। घर के पास प्रशिक्षण मिलने से काम सीखना आसान हो गया है।

सोलन से दुर्गम पंचायतों तक पहुंच रही जैविक खाद

किसानों की आर्थिकी हो रही मजबूत

टीम रीव सोलन

सोलन के किसानों के लिए मिशन रीव आय के अतिरिक्त साधन पैदा करने में कामयाब रहा है। खेतीबाड़ी के साथ –साथ यहां के किसान अब जैविक खाद की बिक्री से भी अपनी आर्थिक मजबूत करने में लगे हैं। सोलन में पिछले करीब तीन माह से मिशन रीव के तहत गांव के किसानों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में जौनाजी पंचायत के दामकारी गांव के मायादत्त द्वारा तैयार खाद को चंबा की दूर दराज पंचायतों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा अश्विनी ,खड्ड के सुरेश, पवन, दीपक कुमार, निशा, सुमन, नैना और अनिल ने भी मिशन रीव के तहत खाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

अब जल्द ही प्रदेश के बाकि जिलों में तक मिशन रीव के माध्यम से खाद की आपूर्ति की जाएगी। यह खाद मिशन रीव के तहत गांवों के किसानों द्वारा तैयार की गई है। खाद तैयार करने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव में दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश के दस जिलों में किसान जैविक खाद बना रहे हैं। किसानों द्वारा तैयार इस खाद को मिशन रीव के माध्यम से बाजार भी प्रदेश के भीतर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रयास से मिशन रीव हिमाचल को जैविक राज्य बनाने के सपने को साकार करने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस काम की ग्रामीण क्षेत्रों में भी खूब सराहना हो रही है। कृषि के अलावा भी सोलन में अन्य कई सेवाएं भी मिशन रीव के तहत प्रदान की जा रही है। इसमें लोगों के घरद्वार तक सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

मिशन रीव के अंतर्गत पूरे हिमाचल में रीव जैविक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई है। इसके प्राप्त करने लिए इन दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें .... 9459584566 और 8219175636, साथ ही आप हमारी वेबसाइट : missionriev.in/www.iirdshimla.org पर लॉगइन कर अधिक जानकारी ले सकते हैं

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम....
...रीव जैविक खाद

20रू. किलो / 40 किलो का कट्टा उपलब्ध है

Parameter	Percentage
PH	7-8
Organic carbon	7.36 - 9
Nitrogen	1.69 - 2
Phosphorus	0.75 - 1
Potassium	1.17 - 1.50
Sulphur	0.042 - 0.70
Zinc	0.0053 - 0.0075
Iron	0.14 - 0.30
Copper	0.0011
Calcium	2.2 - 3
Magnesium	1.03 - 1.20
Boron	0.0012
Manganese	0.0097
Calorific Value	219.96

कृषि को पंख देगा मिशन रीव

युवाओं को सिखाए जांएगे आधुनिक कृषि के गुर

टीम रीव, बिलासपुर

बिलासपुर में अधिकतर किसानों की आय का मुख्य साधन कृषि है। इसके अलावा जिला में पॉलीहाऊस को भी व्यवसाय के तौर पर अपनाने का चलन पिछले कुछ समय से काफी बढ़ गया है। युवा इस ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन कृषि और पॉलीहाऊस में बेहतर फसल के लिए अच्छी किस्म के बीजों और अन्य उपकरणों का प्रबंध करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जानकारी के अभाव में कुछ युवा अपनी योजनाओं को सिरे नहीं चढ़ा पा रहे हैं।

मिशन रीव ऐसे युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए जल्द ही एक अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत युवाओं को उनकी रूची के मुताबिक आधुनिक कृषि के गुर सिखाएं जाएंगे। इसके लिए कहां से बीज और कृषि के अन्य उपकरण प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी मिशन रीव पूरा सहयोग करेगा। इसके अलावा गांव में तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना और उत्पपादों की उचित कीमत दिलाना भी मिशन रीव की प्राथमिकता रहेगी। किसानों को मिशन के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी पूरा सहयोग किया जाएगा।

सरकार की सिंचाई योजना, सोलर पंप, उन्नत किस्म का बीज आदि गांव के लोगों तक पहुंचाने में पूरी मदद की जाएगी। इन सबके अलावा मिशन रीव हर जिले की तरह बिलासपुर में भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर है।

रीव संस्करण दो में मिलेगी बेहतर सुविधाएं

सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहा मिशन रीव

टीम रीव, कांगड़ा

कांगड़ा के लोगों को मिशन रीव संस्करण–दो के तहत अब और भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

संस्करण–दो में लोगों की आवश्यक्ताओं के अनुसार 10 अलग–अलग प्रभाग तैयार किए गए हैं। इन्हीं प्रभागों के आधार पर लोग अपनी आवश्यक्ताओं का ऑनलाइन आकलन कर सकेंगे और मिशन रीव की सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मिशन रीव के पहले संस्करण में लोगों को स्वास्थ्य, ऑनलाइन और जैविक खाद प्रशिक्षण जैसी विभिन्न सुविधाएं दी गई।

इस दौरान मिशन रीव के पहले संस्करण में अपने स्तर पर सेवाएं देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने में भी मिशन रीव ने बेहतरीन कार्य किया।

गांव के लोगों का कहना है कि पहले छोटे से काम कराने के लिए भी बार–बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब मिशन रीव के तहत कम समय में अधिकतर कार्य हो जाते हैं।

बहरहाल, संस्करण दो के तहत किसानों को कृषि योजनाओं की व्यापक स्तर पर जानकारी मुहैया कराने के साथ ही बेहतर पैदावार प्राप्त करने के गुर भी मिशन रीव के तहत बताए जाएंगे। खास बात यह कि जल्द ही किसानों को मृदा जांच की सुविधा भी मिशन रीव के तहत मुहैया करवाई जाएगी।

सेवा प्रभागों के मुताबिक लोग स्वंय कर सकेंगे आवश्कता आकलन

इसके अलावा कुछ समय पहले ही कांगड़ा में तीन जनऔषधि केंद्र भी आईआईआरडी की ओर से खोले गए हैं। इन केंद्रों पर गांव के लोगों को जहां बाजार से बेहद कम कीमत पर दवाईयां उपलब्ध हो रही है वहीं गांव में ही यह सुविधा मिलने से लोगों के समय की भी बचत हो रही है। लोगों को कहना है कि मिशन रीव के तहत लोगों को विभिन्न सुविधाएं अपने गांव में ही आसानी से प्राप्त हो रही है और यह गांव के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

ग्रामीणों को दिया जाएगा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण

टीम रीव, हमीरपुर

शिमला और मंडी के बाद अब जल्द ही जिला हमीरपुर में किसानों को मिशन रीव के तहत ऑयस्टर मशरूम उगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद किसानों को उसकी बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ जो भी किसान मशरूम की खेती करना चाहता है उसके लिए ढांचा विकसित करने और मशरूम उगाने तक मिशन रीव के तहत पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए आईआईआरडी शिमला कार्यालय में जुलाई माह के पहले सप्ताह में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मशरूम प्लांट स्थापित किया गया था। सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद जिला मंडी में भी पायलट आधार पर लगाया गया प्लांट सफल रहा है। अब इस आधार पर जल्द ही हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों में ऑयस्टर मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जैविक खाद की तर्ज पर ही किसानों को मशरूम की बिक्री के लिए किसानों को बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

कुछ समय पहले ही मिशन रीव की ओर से किसानों की समस्याओं को जानने के लिए शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने बताया कि कई बार मौसम के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है। ऐसे में बाजार में उसके सही दाम नहीं मिल पाते हैं इस समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक आय के साधन के तौर पर मशरूम की खेती करने के इच्छुक हैं। लेकिन इसे कैसे लगाना इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसके बाद फिर सवाल यह भी है कि मशरूम उगाने के बाद उसे बेचना कहां है ताकि अच्छे दाम मिल सके। इसे देखते हुए मिशन रीव के तहत गांव में किसानों को ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के गुर सिखाए जाएंगे।

आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा का कहना है कि मिशन रीव के तहत पंचायतों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में अब ऑयस्टर मशरूम की खेती से जोड़कर गांवों की आर्थिकी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

ऑयस्टर, बटन मशरुम के मुकाबले में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है।जल्द ही लोगों को इस की खेती करने की पूरी जानकारी दी जाएगी और मशरूम की अन्य प्रजातियों के बारे में भी बताया जाएगा।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा मिशन रीव

टीम रीव, कांगड़ा

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त करने के लिए मिशन रीव की ओर से विशेष पहल की जा रही है। महिलाओं को उन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जिन्हें अपनाकर वह अपने और अपने परिवार की आर्थिकी मजबूत कर सकेगी। इसके लिए मिशन रीव के तहत महिला मंडलो और महिलाओं से जुड़े अन्य संगठनों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

इसी उद्देश्य से मिशन रीव की ओर से कांगड़ा के शाहपुर के रैत ब्लॉक में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान एनआरएलएम पीआरपी नीशा एवं रेनू ने वीओ फांउडेशन करते हुए एनआरएलएम के तहत शाहपुर में 11 समूह को मिलाकर भोले शंकर महिला ग्राम संगठन बनाया। ग्राम पंचायत चड़ी में बुक कीपिंग, रिवालविंग और नए समूह का आजीविका मिशन के तहत गठन किया।

इस बैठक में महिलाओं को मिशन रीव के तहत ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया कि वह कैसे घर का कामकाज करने के साथ स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं और कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। महिला मंडल की सदस्यों की ओर से मिशन रीव की भरसक प्रशंसा की गई। महिलाओं ने कहा कि योजनाओं के बारे में बात तो सब करते हैं लेकिन इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करना है यह कोई नहीं बताता। लेकिन अब मिशन रीव के तहत यह जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उन महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है जो घरेलु काम काज के कारण कहीं बाहर नहीं जा पाती। मिशन रीव के तहत पंचायत में, यहां तक की घर में ही सभी जानकारी प्रदान की जा रही है।

बिलासपुर में भी बनेगी जैविक खाद

आसान हुई जैविक खेती की राह

टीम रीव, बिलासपुर

मिशन रीव के तहत बिलासपुर की विभिन्न पंचायतों में भी जल्द ही जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर कोई जैविक खाद बनाकर उसकी बिक्री करना चाहता है तो आईआईआरडी की ओर मिशन रीव के तहत उसे वह खाद खरीद कर मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। अभी तक प्रदेश के अन्य जिलों की पंचायतों में ही तीन हजार से अधिक किसानों को जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत लोगों को दिया जा चुका है।

नि:शुल्क प्रशिक्षण से सैंकड़ों किसानों को मिलेगा लाभ

बिलासपुर के घुमारवीं में कुलदीप, सुनीता, बिमला व अन्य लोगों ने बताया कि वह मिशन रीव के तहत खाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रह हैं और कुछ दिन बाद ही जैविक खाद तैयार कर लेंगे। मिशन के तहत यह प्रशिक्षण निशुल्क दिया जा रहा है, जिसका हजारों किसान लाभ उठा रहे हैं। लोग मिशन रीव के इस प्रयास से काफी खुश है। मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने गांव के लोगों को इसका निशुल्क प्रशिक्षण देकर बेहतरीन कार्य किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और न ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे।

सेवाओं का लाभ सदस्यता के उपरांत आवश्यकता आकलन के आधार पर लिया जा सकेगा और आपके जीवन को सरल व खुशहाल बनाने के लिए मिशन रीव है निरंतर तत्पर।

दिल से सेवा दिल से भुगतान

- आवश्यकता आकलन के साथ ही आपके द्वारा स्वीकार्य सेवाओं एवं आवश्यकताओं का रीव को -ऑर्डिनेटर दिल से करेगा निदान और इसके लिए आप भी न्यूनतम निर्धारित भुगतान के बाद दिल से ही करेंगे भुगतान।
- सदस्यता के तीन प्रारुपों में अब आप के सामने है विकल्प : आजीवन सदस्यता, पूर्ववत वार्षिक सदस्यता तथा स्वैच्छिक सदस्यता
- सदस्यों का आवश्यकता आकलन कर , दस प्रभागों में स्वीकृत की गई सेवाओं को घर-द्वार पर ही उपलब्ध करवाया जाऐगा तथा जो सेवाऐं सरकार, प्रशासन अथवा अन्य माध्यमों से उपलब्ध होनी है उनको उपयुक्त स्थान और समय पर हस्तांतरित किया जाऐगा।
- आओ नववर्ष पर शतायु और निरोगी जीवन के साथ-साथ एक सामाजिक सुरक्षा एवं धन-वैभव जीवन की परिकल्पना को मिशन रीव के साथ जुड़कर करें साकार। इस नववर्ष पर रीव के उत्पादों, सेवाओं और मिशन को आगे ले जाने के लिए हम सभी बने समाज के संवाहक।

मिशन रीव की सेवाओं की दी जानकारी

अपनी ही पंचायत में काम करने का मिला मौका

टीम रीव,मंडी

मंडी ज़िले में मिशन रीव के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर सेवाएं प्रदान की जा रही है। सेवाओं के साथ ही मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के सबसे बड़े मिशन की ओर अग्रसर है। ज़िले मे मिशन रीव के तहत पंचायत, खण्ड स्तर एवं ज़िला स्तर पर सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए विशेष बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह की बैठक रिवाल्सर पंचायत में आयोजित की गई। इस दौरान मिशन रीव के साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई।

साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ज़िला में विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया । इससे किसानों में रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद बनाने व उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पंचायतों में मिशन रीव प्रतिनिधि गांव–गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण भी कर रहे हैं। लोगों की मांग पर कम कीमत में फूलों का बीज, मटर तथा मक्की का बीज लागों को उनके घर पर ही प्रदान किया गया। ऑनलाइन सेवाओं के बारे में आम ग्रामीणों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है तथा किस प्रकार ऑनलाइन बिजली के बिल, टेलीफोन एवं अन्य बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है ।

ऑनलाइन सिस्टम भी जान रहे ग्रामीण

मिशन रीव से गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। अगर कोई बाजार से दवाईयां लाना चाहता है तो वह भी मिशन रीव के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा से मिलने से ग्रामीण काफी खुश है।

मिशन रीव बदल रहा गांव की तस्वीर

टीम रीव, कुल्लू

डेढ़ साल पहले मिशन रीव की शुरूआत जिस उद्देश्य से की गई थी उसे साधने में काफी हद तक सफलता मिली है। बात अगर कुल्लू की करें तो कुल्लू में मिशन रीव के तहत कई सुविधाएं मुहैया करवाई गई। कुल्लू में अपने स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने जिला के दूरदराज के गांवों में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक किया वहीं प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच और जरूरी दवाईयां भी घर पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।

आवश्कता आकलन के तहत ऐसे परिवारों की पहचान की गई जिनके लिए बाजार से रोजमर्रा की जरूरत का सामान घर पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे परिवारों को मिशन रीव के प्रतिनिधियों की ओर से सभी सामान उनके घर तक बाजार से कम कीमत पर पहुंचाया गया। अभी भी यह प्रक्रिया लगातार जारी है। पहले लोगों की जरूरतों को जानने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली गई और उनको मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

इसके अलावा लोगों के घरों पर जाकर भी मिशन रीव के प्रतिनिधि आवश्यकता आंकलन कर रहे हैं। इसके लिए अलग से आवश्यकता आंकलन फॉर्म बनाए गए हैं। इसके माध्यम से लोगों की जरूरतों को जानकर उन्हें मिशन रीव की सेवाएं प्रदान की जा रही है।

लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान उनके घर पर ही उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी रीव के तहत व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। गांव के लोगों को जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खाद बनाने से लेकर इसके तैयार होने तक रीव प्रतिनिधि गांव के लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि विकास के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और अगर कोई योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसका भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। किसनों को उन्नत किस्म के बीज व कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराने में सहयोग किया जा रहा है।

नववर्ष के आगमन के साथ ही जिला कुल्लू

घर पहुंच रहा जरुरत का सामान

में मिशन रीव के तहत लोगों को रीव संस्करण दो के तहत दस अलग–अलग प्रभागों के तहत सेवाएं प्रदान की जाएगी। लोग स्वंय आश्यकता का आकलन कर अपनी इच्छानुसार मिशन की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

मिशन रीव के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं से लोगों में भी काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ रहा था लेकिन अब मिशन रीव के तहत उन्हें हर तरह की सुविधाएं घर पर ही मिल रही है। इससे उनके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है।

महिलाओं को दी मिशन रीव की जानकारी

टीम रीव, चंबा

किसी भी क्षेत्र के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। ऐसे में जरूरी है कि विकास को लेकर नई योजनाओं के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया जाए। इसी उद्देश्य से मिशन रीव की ओर से चंबा की विभिन्न पंचायतों में महिला मंडल के साथ विशेष बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पंचायत फेसिलिटेटर लाल देई की ओर से महिलाओं को मिशन रीव के तहत ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। लाल देई ने महिलाओं का बताया कि वह कैसे घर का कामकाज करने के साथ स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं और कैसे अपनी आर्थिकी स्थिति को मजबूत कर सकती है।

महिला मंडल की सदस्यों की ओर से मिशन रीव की भरसक प्रशंसा की गई। महिलाओं ने कहा कि योजनाओं के बारे में बात तो सब करते हैं लेकिन इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करना है यह कोई नहीं बताता।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए विशेष बैठकों का आयोजन

लेकिन अब मिशन रीव के तहत यह सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

महिलाओं का कहना है कि मिशन रीव के तहत बेहद महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौका उन्हें अपने गांव में ही मिल रहा है।

मण्डी में तैयार हो रही जैविक खाद

मिशन रीव ने ग्रामीणों को दिया प्रशिक्षण

टीम रीव, मण्डी

प्रदेश में पिछले काफी समय से जैविक खेती को लेकर योजनाएं बन रही है लेकिन अधिकतर किसानों को अभी जैविक खेती की पूरी जानकारी नहीं है। इस समस्या का समाधान करके प्रदेश को जैविक राज्य बनाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान शिमला (आईआईआरडी) मिशन रीव के तहत अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। मिशन रीव के तहत प्रदेश के गांवों में किसानों और बागवानों को जैविक खाद बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मंडी में भी किया गया। इसके बाद किसान यहां जैविक खाद का भंडार तैयार करने में लगे हैं।

इतना ही नहीं किसानों को जैविक खाद बिक्री के लिए बाज़ार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जिला शिमला, सोलन में ही किसानों ने मिशन रीव के सहयोग से जैविक खाद का अच्छा–खासा भंडार तैयार हो गया है। अब वह मिशन रीव के माध्यम से इसकी बिक्री करके आय भी प्राप्त कर रहे हैं।

यह पहली बार है कि कोई संस्था गांव के लोगों को उन्हीं के घरद्वार पर रोजगार के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने का भी अवसर प्रदान कर रही है। इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत पंचायतों में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती की गई है। संस्था के ये प्रतिनिधि गांवों में ही किसानों और बागवानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन प्रतिनिधियों को आईआईआरडी शिमला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है।

खाद की बिक्री के लिए बाजार भी करवाया उपलब्ध

लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन मिशन रीव ने इसे आसान बना दिया है। आईआईआरडी के प्रबंधक निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा का कहना है कि हिमाचल का विकास तभी संभव है जब गांव के लोगों के पास रोजगार और व्यवसाय के अवसर होंगे। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

कैसे बनती है जैविक खाद

यह तकनीक National Centre for Organic Farming (NCOF) जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है, द्वारा सामने लाई गई है जिसे किसानों तक गांव में मिशन रीव पहुंचाने का कार्य कर रहा है।

सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रचलित अन्य किसी भी प्रकार की खादों में सबसे कम समय में तैयार होती है। साथ ही गुणवत्ता के मापदंडों पर भी यह औरों से आगे हैं। इसे लगभग 30 से 40 दिनों के बीच तैयार कर लिया जाता है। इसका एक मुख्य गुण यह है कि यह ज़मीन के अंदर जाकर मिट्टी के पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता को बढ़ा देता हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाता है।

गांव के विकास को गति दे रहा मिशन रीव

टीम रीव, चंबा

चंबा में मिशन रीव के तहत गांव के लोगों को विभिन्न सुविधाएं गांव में ही प्रदान की जा रही है। पहले बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अन्य काम रह जाते थे। सिलेंडर बुक कराने और लाने की भी परेशानी रहती थी। लेकिन अब गांव के लोगों के यह सभी काम मिशन रीव प्रतिनिधियों द्वारा आसानी से किए जा रहे हैं। बात रोजमर्रा की जरूरत का सामान बाजार से घर पहुंचाने की हो या कृषि उपकरण, खाद अथवा बेहतर किस्म का बीज उपलब्ध कराने की, मिशन रीव सभी कार्यों में अहम भूमिका निभा रहा है।

लोगों का कहना है कि पहले छोटे छोटे घरेलु काम जैसे बिजली का बिल जमा करना, बीज खरीदना, गैस सिलेंडर बुक कराना, ये काम खुद की करने पड़ते थे लेकिन अब मिशन रीव ही यह सारे काम कर देता है। रीव प्रतिनिधि जरूरतों के अनुसार सभी काम समय पर पूरा करके देते हैं। इससे परेशानी कम हो गई है और समय की बचत भी हो गई है।

चंबा में तीन सौ से अधिक लोग मिशन रीव के तहत सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न तरह के उत्पाद भी लोगों को घरों तक पहुंचाए जा रहे है। इनके लिए पहले लोगों को शहरों की दौड़ लगानी पड़ती थी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर किसानों को आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि विभाग की उन सेवाओं के बारे में भी इन किसानों को अवगत कराया जा रहा है जिसका लाभ वे सरकारी तौर पर उठा सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने में भी मिशन रीव के सदस्य गांवों के लोगों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं ।

सफलता के लिए कुछ बातें

- **जीवन में सफलता पाना सभी का एकमात्र लक्ष्य होता है। यदि हम छोटी–छोटी बातों पर ध्यान दे तो हम वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानि हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप भी थोड़ा सा बदलाव अपनी जीवन शैली में लाएँ तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता।**
- **जो भी करो अच्छे से करो :** आपको जो भी काम दिया जाता है उसे उत्कृष्ट करने की कोशिश करें। आपका हर काम आप का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हर काम में पूरी जान लगा कर अपना सौ प्रतिशत परफॉर्म करो। आपका मुकाबला किसी और के साथ नहीं है। आपने पूर्व में जितना किया था उससे बेहतर परिणाम मिले इस पर आपका ध्यान केन्द्रित होना चाहिए।
- **शिकायत करने की आदत अच्छी नहीं :** अगर हम सवाल सुलझाने को तैयार नहीं होंते तो हम भी उस सवाल का हिस्सा बन जाते है। खुद ही समस्या बन जाते हैं। इसीलिए शिकायत करना छोड़ के सामने जो परिस्थिति है उसे स्वीकार करके अपना ध्यान काम पर केंद्रित करना चाहिए।
- **थोड़ा और ज्यादा :** लोगों की अपेक्षा से ज्यादा कुछ करने की, ज्यादा कोशिश करके थोड़ा ज्यादा काम करने की तैयारी रखो। जो लोग ऑउट ऑफ दी बॉक्स सोचते हैं और लोगों के लिए खुद से कुछ अतिरिक्त प्रयास कर लेते है वही लोग आगे जाकर सफल इंसान बनते है।
- **अपनी भूमिका तय करो :** किसी भी परिस्थिति में परिस्थिति के साथ बहते जाना आप के व्यवहार और विकास के लिए अच्छा नहीं है। हर एक चीज़ में सोच समझ के निर्णय लीजिये और बहस की स्थिति में स्वयं को इससे अलग ही रखें। उस भूमिका पर आगे आने वाले समय में डट कर खड़े रहना भी बहुत ज़रुरी है। यह सफलता का सूत्र है जो आप को सफल बनाएगा।
- **फोकस:** सफलता के कदमों में अपना गोल या लक्ष्य स्पष्ट रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य क्या है? आपको स्पष्टतः क्या चाहिये? यह मत भूलो। कुछ भी हो जाये आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए।
- **आपकी संगत से आपकी पहचान :** नेता अच्छा होता है पर उसके सलाहकार बुरे होते हैं। यह वाक्य हम हमेशा सुनते हैं। हम ऐसी परिस्थिति में न फसें इसलिये दोस्त अच्छे और सोच के चुनों। सफल व्यक्ति पर उसके दोस्तों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ज़ाहिर है सफल व्यक्ति के दोस्त भी काबिल और सफल होते है।
- **स्वयं पर विश्वास एवं भरोसा करना :** बहुत बार लोग होशियार और मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। इसका मुख्य कारण है कि वह खुद पर बिलकुल भरोसा नहीं करते। खुद पर विश्वास होना सबसे बड़ी बात है । अगर खुद पर विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से पार की जा सकती है।
- **चरित्र सफलता की कुंजी :** आपका हर एक काम आपके रुतबा बना या बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपको आपके हर एक क्रिया पर पूरी नज़र रखनी होगी। गलती से भी आप कुछ ऐसा न करें जिससे आपके चरित्र पे दाग लग जाये। इंसान का चरित्र उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसीलिए हर एक काम में अपने रुतबे और चरित्र को ध्यान में रखके क़दम बढ़ाना चाहिए।
- **जीवन का असल मक़सद जाने :** खुद को पुछो हम किस लिये जी रहे है। अपना लक्ष्य क्या है? जीना बहुत सुंदर है। ऐसा कहते है कि, कुछ करके असफलता मिलना ये कुछ नहीं करने से कहीं अच्छा है । इसलिये हमारे जीने का मक़सद हमें ढूंढना ही होगा।
- **मुस्कुराहट से करें दिन की शुरुआत :** दिन की अच्छी शुरुआत कैसी होगी, ये हमें स्वयं ही तय करना होगा। बहुत बार छोटी बातों से मूड़ खराब हो जाता है और हम कुछ नहीं करते। बस चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिये सुबह उठने के बाद सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें।

क्या होता है गले का संक्रमण

गले का संक्रमण एक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण होता है जो गले में विकसित होता है। एक अनुमान के अनुसार इसके हर वर्ष लगभग 30 मिलियन केस डायग्नोज किये जाते हैं। हालाँकि, वयस्कों की तुलना में बच्चों और प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी के लक्षणों से जूझ रहे लोगों को गले का संक्रमण होने की सम्भावना अधिक होती है लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। गले के संक्रमण का पता लगाने का एकमात्र रास्ता है की अपने डॉक्टर को दिखाएँ और प्रोफेशनल मेडिकल टेस्ट कराएँ। परन्तु, डॉक्टर को दिखाने से पहले आप लक्षणों को पहचान सकते हैं और उनके आधार पर सुझाव दिया जा सकता है कि आपके गले में संक्रमण हुआ है या नहीं।

- गला खराब होना, गले में काँटे जैसे पड़ना, खराश महसूस होती रहना आदि है तो सामान्य प्रक्रिया, लेकिन तुरंत ध्यान न दिया जाए तो गंभीर परिणाम देती है।
- वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण से गला ख़राब हो जाता है, फ्लू हो तो गले पर असर होता है। ज्यादा ठंडा पेय पीने से, ठंडे पर गरम पीने से या गरम पर ठंडा पीने से तथा पसीने में पानी पीने से भी गला ख़राब हो जाता है।
- गला दो तरह से खराब हो सकता है, पहला तो यह कि अगर कौक्सैकी वायरस का संक्रमण हो तो टांसिल व तालू पर छोटी–छोटी गाँठें नजर आती हैं और इनमें पीप भर जाता है, बाद में ये फूट जाती हैं और गले में बहुत दर्द होता है।
- दूसरा कारण, स्टैप्टोकौकल बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, इससे टांसिल्स में सूजन आ जाती है, गले में सफेद परत सी जम जाती है, बुखार भी आ सकता है, तबीयत ठीक नहीं लगती और साँस में बदबू पैदा हो जाती है, जो स्वयं को भी महसूस होती है।
- यदि किसी को बुखार हो तो भी गले में खराबी आ जाती है और कुछ भी निगलने में परेशानी होती है।
- कई बार रोगी के छींकनें, खाँसने से जीवाणु वायु में फैल जाते हैं और पास वाले स्वस्थ व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेते हैं। जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो दो–तीन दिन बाद रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं । कई लोगों का तो पूरा गला लाल हो जाता है और थूक तक निगलने में परेशानी होती है।
- जब गला खराब हो जाता है तो लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। पूरा कंठ लाल हो जाता है, टांसिल बढ़ जाते हैं, सर्दी लगकर बुखार भी आ सकता है। गले का दर्द कान तक महसूस होता है, नाक से पानी बहता है या नाक बंद हो जाती है, कभी–कभी सूखी खाँसी भी चलती है।
- उपचार करने से पूर्व डॉक्टर यह जाँच करता है कि इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल, उसी के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला

अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

20 ऐसे कानून जो हर भारतीय को जानना चाहिये

आपको इस अंक में बताते हैं कि कुछ कानून आपके लिए जानने अतिआवश्यक है जिससे आप किसी अधिकारी या पुलिस के सामने उनकी मनमानी का विरोध कर सकते हैं।

- ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है।
- किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है।
- कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों न हो, आपको फ्री में पानी पीने और वाशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है।
- कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा।
- एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है। चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या न पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता है कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है।
- कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है।
- टैक्स उल्लंघन के मामले में, कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है?
- तलाक इन आधारों पर लिया जा सकता है, **हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता–पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है।**
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर दो व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटर साइकिल से चाबी निकालना गैरकानूनी है इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं।
- केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है।
- बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाये तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40लाख रुपये तक की सहायता ले सकते हैं।
- अगर आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है।
- यदि आपका किसी दिन चालान काट दिया जाता है तो फिर दुबारा उसी अपराध के लिए चालान नहीं काटा जा सकता है।
- कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नहीं मांग सकता है। लेकिन उपभोक्ता, अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है।
- यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन 3 साल के बाद आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।
- यदि आप सार्वजनिक जगहों पर 'अश्लील गतिविधि' में संलिप्त पाये जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है। लेकिन 'अश्लील गतिविधि' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरूपयोग करती है।
- यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं । साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिये जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 साल का अंतर होना जरूरी है।
- यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिये जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है । आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर डालें therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

परंपराएं, धर्म व अध्यात्मिकता

सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने न केवल भौतिक उन्नति की है अपितु मानसिक रूप से भी लगातार सूक्ष्मतर होते रहना निरंतर प्रगति का सूचक मानने लगा। यह क्रम भ्रांतियों से आस्था, आस्था से विश्वास, विश्वास से नियम(परंपरा) तथा नियम से सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में चलता रहा। दर्शन के अभाव में मनुष्य यह नहीं भांप पाया कि वास्तविकता की दिशा किस ओर है। जो जीवन पद्धति हमें कुछ महापुरूषों से विरासत में मिली है उसको सही तरीके से परिभाषित कर आमजन तक पहुंचाने में मानव समाज बहुत नाकाम रहा जिसका परिणाम यह रहा कि आज भी सामान्य जनसमुदाय सामाजिक भ्रांतियों के भय में जीवन यापन कर रहा हैं। ज्ञान के वैज्ञानिक विश्लेषण को विस्तार देने के कार्य में हम दशकों से सामाजिक चेतना लाने के प्रयास में शिक्षित वर्ग में भी सफल नहीं हो सके, यह एक चिंताजनक विषय है। इसका ताजा उदाहरण जिला शिमला के ननखड़ी क्षेत्र में 90 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया 'शांत यज्ञ' है। क्षेत्र की रक्षा के लिए इस यज्ञ में लगभग 150 बकरों और मैमनों की बलि देकर क्षेत्र को रक्तरंजित कर लिया गया। ऐसे आयोजन का एकमात्र तर्क यह है कि ऐसे आयोजन पहले भी होते रहे हैं। ऐसा होने से कितनी शांति अब इस क्षेत्र मे आएगी, इस बारे में मंदिर के प्रबंधन से जुड़े तथा तामसिक वृतियों की जकड़न में फंसे समुदाय के शिरोमणियों से ही जानकारी मिल सकती है। अपनी झोली भरने के लिए आतुर पांडित्य प्रदर्शन करने वाले तथाकथित विद्वानों ने ऐसी तामसिक परंपराओं को बनाए रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में योगदान दिया। राज्य तथा प्रशासन अपने दायित्व से इस पहलु को पहले ही अलग कर चुका है कि कुरितियों में जकड़ी लाचार जनता को सही मार्ग दिखाना भी राज्य का उत्तरदायित्व है। यह स्थिति कई राज्यों में है जहां महिलाओं, जाति वर्गों व पशुयों के साथ क्रूरता का बर्ताव धार्मिक परंपराओं के अधीन होता रहता है और राज्य मूक दर्शक बनकर देखता रहता है तथा यह प्रतीक्षा करता रहता है कि कोई प्राथमिकी पंजीकृत करे तो कानून–व्यवस्था कुछ हिलने का प्रयास करे।

यहां पर धर्म को जानना आवयश्क है जो लोगों को जीवन पद्धति देता है। आजकल धर्म को लोग मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा तथा गिरिजाघरों से संचालित होने वाले क्रियाकलापों से जोड़कर देखने लगे हैं। वास्तव में धर्म वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्य कई प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सके। इस व्यवस्था में मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा तथा गिरिजाघर आदि स्थान मानव मुक्ति की प्रयोगशालाएं होनी चाहिए थी जबकि वास्तव में हुआ कुछ और ही। इन प्रयोगशालाएं में जिसका प्रयोग किए जाए वह है आत्मिक उन्नति की क्रियाएं जो कई सदियों के आविष्कार के बाद हमारे महर्षि हमें धरोहर में दे गए हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी करें, जैसा भी करें, जहां भी करें, सब अविद्या है। किसी भी तथाकथित धार्मिक कार्य को करने से पहले हमें यह स्वयं से पूछना होगा कि किए जाने वाला कार्य हमें बंधन की ओर ले जा रहा है या मुक्ति की ओर। यहां पर बंधन और मुक्ति का भी संक्षिप्त तात्पर्य जाना जा सकता है। वह समस्त कार्य जो हमारे काम, क्रोध, मोह व अहंकार की अवस्था में वृद्धि कराते हैं, बंधनयुक्त कहे जा सकते हैं और इनके विपरीत मुक्ति की दिशा में ले जाने वाले। आगे चलकर वे समस्त कार्य जो आसक्ति पैदा करते हैं, बंधनकारी कहे गए हैं। अतः आसक्तिहीन कार्य ही 'कार्यम् कर्म' अर्थात् किए जाने वाले कार्यों में आते हैं जो बंधन पैदा नहीं कर सकते। यही आध्यात्मिकता है जहां हम अपनी आत्मा को आवागमन से मुक्त करने के प्रयास करते हैं अर्थात हम आत्मानुकूल कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसके अतिरिक्त बंधन में जकड़ी अपनी आत्मा को हमें पुनः बंधन में डालने के कार्य करते हैं। लेकिन आज की तीव्र दौड़ के इस दौर में इन बातों को जानने तथा विशलेषण करने का समय किसके पास।

लेकिन हम इतना भी जान लें कि हमारी भलाई अपने आस–पास के लोगों, वनस्पति और पशु–पक्षियों के संतुलित समीकरण में ही निहित है। अतः हममें संवेदनशीलता होनी अनिवार्य है अन्यथा अपने स्वार्थ व अहंकारवश हम अपने जीवन के सुख को खोने के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

Social Enterpreneurship - A Catalyst for Inclusive Growth

Muhammad Yunus, 2006 Nobel Peace Prize awardee and founder of Grameen Bank, once in an interview said "poverty is an artificial creation. It doesn't belong to human civilisation, and we can change that, we can make people come out of poverty. The only thing we have to do is to redesign our institutions and policies."

That what social entrepreneurship is about: creating business models revolving around low-cost products and services to resolve social inequities. And the realisation that social progress and profit aren't mutually exclusive has led to many social ventures taking root in India as well, which includes the India's well know brand Amul, SEWA and others. But the days of easy funding are over. Social entrepreneurs are the ones who redefine entrepreneurship by working for a social cause that generally gets oppressed in a mad rush towards inventing products that can comfort human living. Surprisingly, they continue to launch social enterprises with a vengeance.

Despite being the second fastest growing economy after China, India is home to around 40% of the world's poor, with just under 30% of the population living below the poverty line (CIA website). The country is still battling with socio-economic issues like illiteracy, malnutrition, and poor healthcare. Other issues include relatively low productivity and deep rural-urban and caste divisions. Despite impressive growth, the dent on poverty has been marginal. Lack of access to quality education constrains youth employability. Almost a quarter of the population is illiterate and about 98% of the young people enter the market without adequate skill sets (CIA website). This is a major constraint in realising the potential which India's large young population offers.

The challenge for India is to attain high growth and also to make sure it is inclusive. This inclusion cannot be merely about income but also about the services that people need – healthcare, financial services, education, water, and sanitation amongst others. Social entrepreneurs fill key gaps in providing basic services and goods to poor. Development Marketplace is a competitive small grants program that identifies and funds innovative, development projects with a high potential for social impact.

The common thing among the historically worthy social entrepreneurs is they have identified sustainable solutions to daunting social problems that have fundamentally changed society and humanity to a great extent.

India has the world's second largest labour force of 516.3 million people and although hourly wage rates in India have more than doubled over the past decade. With an estimated population of 1.2 billion people, this means that every third Indian is bereft of even basic necessities like nutrition, education and health care and many are still blighted by unemployment and illiteracy. Social entrepreneurs can help alleviate these issues by putting those less fortunate on a path towards a worthwhile life. Rather than leaving societal needs to the government or business sectors, they can solve the problem by changing the system.

The need for and significance of social entrepreneurs is imbued with multiplicity of justifications. Just as business entrepreneurs change the face of business, social entrepreneurs act as the change agents for society, seizing opportunities others miss and improving systems, inventing new approaches, and creating solutions to change society for the better. While a business entrepreneur might create entirely new industries, a social entrepreneur comes up with new solutions to social problems and then implements them on a large-scale for the benefit of the humanity.

Experts feel that social-focus startups will continue to thrive in India. Bringing lowcost services such as banking, healthcare, finance, etc. to underprivileged sections of society is definitely a big opportunity as well as a necessity. Rural, small-town and lower-income consumers constitute a large market waiting to be tapped, but it is necessary for social entrepreneurs to get past language, literacy and geographical barriers. The current environment has also complicated the mix. No market is immune to the global meltdown. If that is true, companies working for this block of the pyramid would be affected as well. The answer may well lie in technology.

Anand Nair, Managing Editor
anand@iirdshimla.org

राजनीतिक अनपढ़ता देश को ले डूबेगी

कर्ज़ा माफी–माफी खेल रहे हैं राजनैतिक दल

आमजन की गाढ़ी कमाई को सत्ता की भूख मिटाने के लिए किया जा रहा उपयोग

हेमराज चौहान (सहायक संपादक)
chauhan.hemraj09@gmail.com

जिस देश का राजनैतिक ढांचा अदूरदृष्टि और अपरिपक्कवता के आधार पर संचालित हो रहा हो, उस देश का भविष्य कितना सुरक्षित है, यह शायद हमारे देश के कर्णधार नहीं समझ सकते हैं। कुर्सी के लिए जिस हद तक गिरना पड़े, हमारे कर्णधार गिरने को तैयार हैं। वर्तमान में देश में जो माहौल बना है, उससे भविष्य के लिए अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। केन्द्र सरकार मज़बूत बहुमत में देश को विकास की पटरी पर लाने के लिए कृतसंकल्प दिख रही है लकिन उनकी पटरी पर चुनौतियों के बड़े–बड़े पत्थर रोड़ा अटका कर खड़े है। हो भी क्यों नहीं..... आख़िर विकास की लौ 4 से 5 वर्षों से तो नहीं जगाई जा सकती है। और देश के नागरिकों की सुख–सुविधाओं का एकमात्र लक्ष्य भी सरकार के मूल उद्देश्यों में होना ही चाहिए। परन्तु ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष अपने मूल को छोड़कर कुर्सी–कुर्सी खेल रहे हैं और देश हित को किनारे रख दिया है। सारा खेल कुर्सी बचाने और खोई कुर्सी पाने के बीच खेला जा रहा है। इसके लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े..... ये तथाकथित माननीय तैयार बैठे हैं।

किसानों की कर्ज़माफी..... बंद आंखों से निशाना साधना

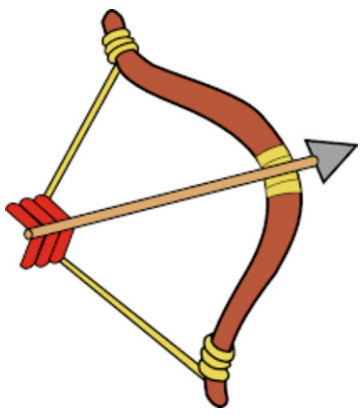

अभी हाल की के चुनावों में जो कुछ हुआ उसे देश का प्रत्येक वर्ग अपने–अपने स्तर पर देख रहा था। बुद्धिजीवी और सोशल मिडिया के स्थाई एवं काल्पनिक प्रेमियों ने भी अपने विचार खुल कर सामने रखे। तीन राज्य जिनमें उनके आकार के अनुसार दो को तो डायनासोर राज्य कहा जाता है, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर सत्ता के लिए दीर्घ प्रतीक्षारत कांग्रेस ने सरकार बनाकर राहत की सांस ली। किंतु इस जीत के भी कई मायने रहे। एक तो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों से लगातार बीजेपी सत्ता पर काबिज़ थी तो राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात सत्ता परिवर्तन की रस्म निभाई गई। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के कर्ज़माफी को लेकर रहा जिसे कांग्रेस ने खूब भुनाया। राहुल गांधी ने अपने भाषणों की शुरुआत ही किसानों के कर्ज़माफी को 10 दिनों में करने के वायदे के साथ की। किसानों को लुभाना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। हो भी क्यों न? किसान इस देश का अन्नदाता और भाग्यविधाता है। किसानों की चिंता सीधे हमारे भविष्य से जुड़ी हैं। लेकिन चुनावों से 6 महीने पहले ही क्यों किसानों की चिंता होती है..... यह एक यक्ष प्रश्न है । सारे चुनाव, नेता, घोषणाऐं किसान और उनके खेतों के आसपास ही घूमती रहती है। पूरे पांच वर्ष कारगर नीति और योजनाओं पर किसी भी सरकार का ध्याना केंद्रित ही नहीं हो पाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या हमारे नेता यह जानते हैं कि किसानों की कर्ज़माफी के नियम–कायदे हैं और यह देखना अतिआवश्यक हो जाता है कि बैंकों से हज़ारों करोड़ों का किसान कर्ज़ किन शर्तों और पैमानों पर चुकता किया जाना है?

मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी के कहने पर शपथ लेते ही कुर्सी पर बैठ कर पहली फाइल जो हस्ताक्षरित की, वो प्रदेश के किसानों की कर्ज़माफी की ही थी। इसका अभिप्राय क्या यह है कि कमलनाथ ने जो काम सत्ता में आते ही बिना कैबिनेट की बैठक किए आंखे बंद कर कर दिया..... उसे करने के लिए मध्यप्रदेश जनता के मामा शिवराज चौहान 15 वर्ष में भी असहाय रहे। हालांकि शिवराज चौहान जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में कुछ नायाब योजनाओं एवं किसानों व महिलाओं के विकास के लिए विशेष रुप से जाने जाते हैं तथापि पूरे प्रदेश के किसानों का कर्ज़ माफ करने में उनकी असमर्थता समझने का विषय है। उधर छत्तीसगढ़ में भी किसानों का कर्ज़माफ कर दिया गया तथा राजस्थान में भी इसी परंपरा को कांग्रेस ने जारी रखा। उधर बीजेपी ने भी चुनावों को देखते हुए इसी पंरपरा को अपनाना आरंभ कर दिया और हरियाणा आदि बीजेपी शासित राज्यों में भी कर्ज़माफी का उद्घोष सुनाई दिया।

ये है आंकड़े..... देश बर्बाद हो सकता है

मध्य प्रदेश में लगभग 74 हज़ार करोड़ का कर्ज़ किसानों ने लिया है। और राहुल गांधी यदि अपने मुख्यमंत्री को आदेश देकर सारा कर्ज़ माफ करवा ही रहे हैं तो मध्यप्रदेश का राजकोषीय घाटा 1 लाख करोड़ से अधिक का हो जाएगा। क्या राहुल गांधी जानते हैं कि यह घाटा कैसे पूरा होगा?

छततीसगढ़ में सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2018–19 के लिए राजकोषीय घाटा करीब 10 हज़ार करोड़ रुपये का होगा। जबकि अभी तक छत्तीसगढ़ में किसानों पर लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ है। अब जैसा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ये सब माफ किया जाए तो राजकोषीय घाटा बढ़कर 23 हज़ार करोड़ रुपये हो जाएगा।।

पूरे देश में किसानों का कर्ज़ लगभग 14 लाख करोड़ रुपये का है। जबकि वित्त वर्ष 2018–19 के लिए देश की कुल अनुमानित आय लगभग साढ़े 22 लाख करोड़ रुपये है। अब 14 लाख करोड़ यदि किसानों के कर्ज़माफी पर भुगतान किये जाते हैं तो कुल बचे 10 लाख करोड़ के आसपास। इससे देश कैसे चलेगा..... यह सत्ता और विपक्ष को बताना होगा।

गुजरात में बीजेपी सरकार ने ग्रामीण परिवारों का 652 रुपये के विद्युत बिल माफ करने का निर्णय लिया है। तो क्या अब बिजली, पानी के बिल भी माफ कर सरकार वोट की नई परंपरा को लागु करना चाहती है? उड़ीसा में बीजेपी ने सरकार बनने पर किसानों का कर्ज़ माफ करने का वायदा किया है। वहीं असम में बीजेपी सरकार ने 650 करोड़ रुपये के लगभग आकर्षक योजनाओं का ऐलान किया है।

देश का सबसे बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग के पास भी वर्तमान में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज़ है जो कि विभिन्न श्रेणियों में हैं जैसे कि कार लोन, घर के लिए लोन, शिक्षा आदि–आदि। उधार की ज़िदगी में वोट की राजनीति ने एक नया चलन शुरु किया है जो कि आगे चल कर कैंसर की तरह लाईलाज हो जाएगा। अब लोन लेकर कोई भी चुकता नहीं करेगा और चुनावों में इसे माफ करने की परंपरा का वहन होगा। पांच साल के लिए आने वाले नेता किस प्रकार देश को गुमराह कर रहे हैं, इसे समझने की आवश्यकता है।

क्या किसानों का कर्ज़माफी फॉर्मूला इश के अन्नदाता के उत्थान एवं विकास का आधार हो सकता है? या इस परंपरा को आरंभ करने के साथ ही भविष्य के लिए अति विकट स्थितियों का सामना करना होगा। यह बात समझने के लिए राहुल गांधी को अब परिपक्कवता की श्रेणी में आकर सत्ता की लालसा और देशहित में अंतर को समझने की आवश्यकता है। यही बात प्रधानमंत्री मोदी को समझनी होगी कि किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो यह कहीं न कहीं शोचनीय विषय है। कर्ज़माफी से यदि सरकार और विपक्ष को लगता है कि किसान आत्मनिर्भर और साधन संपन्न हो जाऐंगे तो इसे इस देश की विडंबना ही कहा जाना उचित होगा। क्या सरकारें नहीं समझ पा रही है कि किसान को उचित समय पर कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। किसान को सही और उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता होती है। किसान को वर्तमान में बेहतर गुणसंपन्न खादों एवं सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता है। किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम एवं आकर्षक एवं स्थाई फसल का न्यूनतम मुल्य निर्धारित होना चाहिए। किसान अपनी सभी प्रकार की फसलों की बीमा को सुनिश्चित बना पाए, ऐसी व्यवस्था क्या सरकार की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? जिन किसानों के खेतों में बाढ़ अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाती है, उनके लिए न केवल कर्ज़माफी बल्कि उचित मुआवज़ा एक स्थाई नीति के तहत दिया जाना चाहिए। इससे बेबस अन्नदाता की आत्महत्याओं के पाप से हम लोग भी कुछ तो उऋण हो पाऐं। संपूर्ण कर्ज़माफी इसका समाधान नहीं है। क्योंकि सत्ता में आने के लिए राजनैतिक दल किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसलिए देशहित को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जो किसान ग़रीब हैं और एक सीमित ज़मीन के मालिक हैं तथा उनकी लोन लिमिट के अनुसार कर्ज़ चुकता नहीं हो पा रहा है, उन्हें ही इस दायरे में लाना होगा। अन्यथा इस कर्ज़माफी की परंपरा में अब एक नई रिवायत शुरु होगी। चुनावों से पहले अच्छा लोन ले लो और उसके बाद चुनावों के दौरान सरकार और राजनैतिक दलों पर दबाव बनाया जाए तथा लोन माफ कर अगले चुनावों का इंतज़ार किया जाए। इसे दूसरे शब्दों में वोट बेचना ही कहा जाता है। यदि वोट उसे दिया जाएगा जो कर्ज़माफ करेगा, मतलब वोट की कीमत कर्ज़माफी। तो क्या हम अपने संविधानिक धर्म और आस्था को बेच रहे हैं?

मुफ्त इस लोकतंत्र में कुछ नहीं

किसानों और बिजली या पानी आदि के कर्ज़माफी के दायरे में आने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मुफ्त कुछ नहीं होता। यह आपकी ही जेब से पूरा किया जाएगा। मंहगाई और टैक्स आदि से लोग जब दुबारा परेशान होंगे तो यह समझ आऐगा कि बैंकों को करोड़ों का कर्ज़ यूं ही माफ नहीं किया गया था। राहुल गांधी शायद ये भूल रहे हैं कि 2014 से पूर्व 10 वर्षों तक वो भी सत्ता में रहे थे। साथ ही अधिकतर राज्यों में उनकी ही सरकारें थी। तो उन्होंने कितने राज्यों में किसानों के संपूर्ण कर्ज़माफ किए थे? यानि अब सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उधर बीजेपी 2014 से पहले विपक्ष में थी और हर रोज़ किसानों के कर्ज़माफ करने का सरकार पर दबाव बनाती रही। आज सत्ताधारी होने पर संपूर्ण कर्ज़माफी पर चुप्पी साध ली। ये राजनैतिक दल किस प्रकार आम जनता का मनमर्दन कर बेवकूफ बना रहे हैं, यह चिंतनीय है। सरकार के पास जो टैक्स नागरिकों से जमा होता है उससे देश का विकास होता है। संभवतः इस बात को ये माननीय समझते भी हैं। परंतु सत्ता से दूरी न सह पाने के कारण अपरिहार्य एवं अनुचित वायदों को लोगों के मध्य रखकर गुमराह करने की परंपरा इन राजनैतिक दलों की लालसा को दर्शाती है। अब किसान भी पीछे क्यों रहे? जब जीत का पैमाना यह बन जाएगा कि कर्ज़माफ तो करना ही पड़ेगा तो उसी हिसाब से अपना समर्थन भी किसान तय करेंगे।

देश सबका.....तो फिर ये आर्थिक असंतुलन क्यों

न्यूनतम मुल्य निर्धारण में एक रुपया बढ़ौतरी पर भी सरकार के पसीने छूट जाते हैं जबकि माननीयों की मासिक तनख़्वाह, भत्तों एवं शानौशौकत के लिए प्राप्त सुविधाओं में कई गुणा बढ़ौतरी पर क्या पक्ष, क्या विपक्ष. .... दोनों ही समर्थन में मेज थपथपा कर कुछ क्षणों में ही उसे कानून की शक्ल में ले आते हैं। न कोई विरोध, न ही कोई आम जनता की स्वीकृति। तो क्या नीति निर्धारकों को यह संवेधानिक अधिकार मिल गया है कि जब चाहे, अपनी सुविधानुसार अपनी तनख़्वाह और भत्ते तय करें और जो किसान भोर से उठकर सारा दिन तपती गर्मी में खेतों में अपना हांडमास गलाता है..... उसके लिए न्यूनतम मुल्य का एक रुपया भी बढ़ाने में सरकार की नींद हराम हो जाती है। किसानों को पहले आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है..... फिर हंगामा बरपता है तो कभी किसानों को कर्ज़माफ या न्यूनतम मुल्य में इज़ाफा या अन्य कोई लुभावनी सी घोषणा। आज भी किसानों को खेती के उपकरणों के लिए सब्सिडी के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। सब्सिडी में भी अतिआवश्यक उपकरणों को नहीं रखा गया है। तो क्या माननीय इस बात से अनभिज्ञ है? जब चुनाव आता है तो ये देश के कर्णधार चीख–चीख कर किसानों और बेरोजगारों के लिए वायदे करते हैं और सत्ता में आते ही राज्य और केन्द्र सरकारों को दोष देते–देते पूरे पांच वर्ष पूरे कर लेते हैं। क्या किसान चुनावों के लिए आकर्षक मोहरा है जिसे कोई भी अपनी–अपनी चाल के तहत मनमुताबिक चलता रहेगा? माननीयों को यदि किसानों की इतनी ही पीड़ा है तो अपनी तनख़्वाह और भत्तों से किसानों के लिए मासिक तौर पर कुछ पूरे देश में क्यों योगदान नहीं देते? जो रात–दिन धूप में तपता और पसीने में नहाता है उस किसान के लिए सरकार की बेरुख़ी चिंता का विषय है। पक्ष और विपक्ष की भूमिका शतरंज नहीं कि बाजी चाल और मोहरों में फंसी रहे। यह राष्ट्र है और इसका संचालन कुशल शासक और एक समझदार विपक्ष के संतुलन का परिणाम होता है। कुर्सी देश नहीं है..... इसे नासमझों को समझ लेना चाहिए।

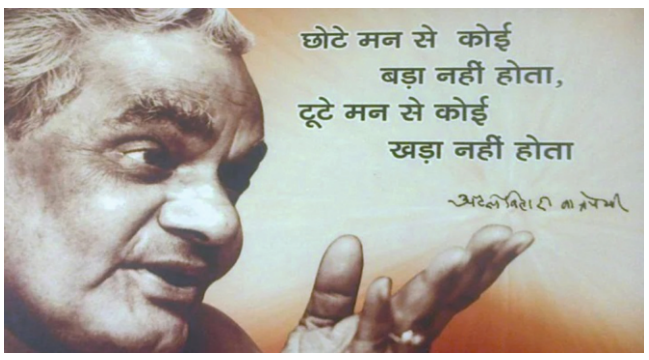

हिमाचल के आंगनबाड़ी केंद्रों में बन सकेंगे आधार कार्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में लोग अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आधार कार्ड बनवा सकेंगे। नए साल में लोग घर–द्वार लोग आधार कार्ड अपग्रेड भी करवा सकेंगे । लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सुपरवाइजरों को भी इसकी जिम्मेदारी दे दी है ।

इसके लिए प्रदेश के 234 केंद्रों को बायोमीट्रिक स्कैनर, वेब कैमरे और जीपीए उपकरण भेज दिए हैं । कार्ड बनाने के लिए सूबे के हर सीडीपीओ कार्यालय में लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट भी दिए गए हैं ।

सरकार के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने भी आधार कार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी है । इसके लिए आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों और कार्यकर्ताओं को चयनित कर पहले फेज की ट्रेनिंग पूरी करवा दी है ।

अब स्वास्थ्य केंद्रों में भी होगी सर्जरी, आंखों–गायनी के ऑपरेशन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य सरकार ने पीएचसी और एचएससी को वेलनेस केंद्र बनाने का फैसला लिया है । इन केंद्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवाएं देंगे । प्रति पीएचसी में 15 से 20 बेड लगाए जाएंगे। सर्जरी, आंखों, गायनी के ऑपरेशन भी इन्हीं केंद्रों में हो सकेंगे । 31 मार्च तक सरकार हिमाचल के 132 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों को वेलनेस केंद्र बनाएगी। चंबा जिले के समोट और सुंडला में वेलनेस केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2022 तक सभी केंद्रों में यह सुविधा मुहैया होगी।

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने यह जानकारी आयुष्मान भारत के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए हेल्थ व वेलनेस सेंटर को क्रियान्वित करने के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से हिमाचल के 21 लाख से अधिक लोग पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवच के दायरे में आ चुके हैं। परमार ने कहा कि टांडा और आईजीएमसी शिमला में चिकित्सकों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के बाद सोलन में भी यह साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं । लगभग 350 पदों को इन साक्षात्कार के माध्यम से भरा जा रहा है ।

शिमला को मिलेगा एक करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी सीएम ने रखी चाबा योजना की आधारशिला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सतलुज के चाबा से अगले साढ़े चार माह के भीतर एक करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी शिमला पहुंचने लगेगा । मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को दस एमएलडी की क्षमता वाली चाबा उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखी ।

योजना पर करीब 69 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे । इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईपीएच विभाग को निर्देश दिए कि अगले 135 दिनों के भीतर इसका काम पूरा किया जाए । अगले साल पहली मई से शिमला शहर को सप्लाई शुरू हो जानी चाहिए ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से शिमला शहर में पानी का संकट नहीं रहेगा। कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में पेयजल योजनाओं पर 275 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रही है ।

राज्य में 90 प्रतिशत घरों को पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा रही है जो राष्ट्रीय औसत 43.5 प्रतिशत से कहीं अधिक है । राज्य सरकार ने 4751 करोड़ रुपये की जल संग्रहण परियोजनाएं प्रस्तावित की थी जिसकी केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है । मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन्नी और तत्तापानी क्षेत्र में जल क्रीड़ाओं की अपार संभावनाएं हैं। सुन्नी, तत्तापानी, करसोग, जंजैहली और शिकारी माता को पर्यटन सर्किट की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा ।

सीएम ने सुन्नी बस अड्डे का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए । मुख्यमंत्री ने गौडु–पलघार सड़क और घैणी–तबोग सड़क के लिए दस–दस लाख रुपये देने की घोषणा की ।

नए साल पर सैलानियों को तोहफा देगा रेलवे इस संग्रहालय तक चलेंगी शिमला आने वाली तीन ट्रेनें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व धरोहर घोषित कालका–शिमला ट्रैक से होकर हिल्सक्वीन शिमला आने वाले सैलानियों को रेलवे नए साल पर नई सौगात देने जा रहा है । 15 जनवरी से पहले शिमला आने वाली तीन ट्रेनों का संचालन बाबा भलखू रेल संग्रहालय तक शुरू कर दिया जाएगा ।

बाबा भलखू रेल संग्रहालय (शिमला ऐक्सटेंशन) तक ट्रेनों का संचालन शुरू करने के लिए विंटर फील्ड के नीचे रेलवे पार्किंग के पास ट्रैक के इर्द गिर्द खड़ी होने वाली गाड़ियों को हटा दिया है ।

गाड़ियां ट्रैक की ओर खड़ी न हो इसके लिए लोहे के एंगल गाड़ दिए गए हैं । ट्रैक पर अतिक्रमण न हो इसके लिए फेंसिंग करने की भी तैयारी है । रेल म्यूजियम और रेलवे कार पार्किंग के बीच का गेट भी बदल दिया है । रेल ट्रैक से गेट की दूरी पहले जहां ढाई मीटर थी वहीं अब इसे बढ़ा कर साढ़े तीन मीटर कर दिया है, ताकि आसानी से गाड़ियां यहां से होकर गुजर सकें । ट्रेन खड़ी करने के लिए रेल म्यूजियम के प्लेट फार्म और साइडिंग की जांच भी की गई है । शिमला रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो से रेल म्यूजियम के प्लेटफार्म नंबर एक तक गाड़ियों का संचालन होगा ।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिए थे निर्देश

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 23 जून को शिमला रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान रेल अधिकारियों को शिमला आने वाली ट्रेनें को शिमला ऐक्सटेंशन तक चलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए थे । इसके बाद 4 जुलाई को शिमला रेलवे स्टेशन से बाबा भलखू रेल संग्रहालय तक ट्रेन चलाने का सफल ट्रायल किया गया ।

850 मीटर है स्टेशन से म्यूजियम की दूरी

शिमला रेलवे स्टेशन से रेल संग्रहालय की दूरी 850 मीटर है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे (कालका–शिमला सेक्शन) की ओर से इस ट्रैक पर गाड़ी चलाने के लिए ट्रैक फिटनेस सर्टिफिकेट मिल चुका है ।

लोगों को नहीं भा रहे टीसीपी के कानून, उठने लगी ये मांग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में शामिल की गई पंचायतों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के कायदे कानून नहीं भा रहे हैं ।

भवन निर्माण के नियम पेचीदा होने पर अब क्षेत्रवासी टीसीपी से बाहर करने की मांग करने लगे हैं। सचिवालय में करीब 70 क्षेत्र की जनता से सरकार से क्षेत्र को बाहर करने का मामला उठाया है । हालांकि पहले इक्का दुक्का आवेदन सचिवालय आते रहते थे लेकिन अब आवेदन की संख्या ज्यादा आने पर अधिकारी इस मामले को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उठाने जा रहे हैं ।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में कुल्लू दौरे के दौरान लोगों को आश्वस्त किया था कि टीसीपी में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के बारे में सरकार उचित निर्णय लेगी । शहरी विकास मंत्री ने भी इस मामले को मुख्यमंत्री से उठानी की बात कही थी, लेकिन अभी तक आवेदन करने की फाइल मंत्री ने नहीं मंगवाई है ।

सरकार ने कई पंचायतों के गांव को टीसीपी में शामिल किया है। इन लोगों को सीवरेज, पानी, स्कूल, परिवहन सुविधा, पब्लिक पाथ, सड़कों की हालत में सुधार खेल मैदान आदि सुविधाओं को झांसा दिया गया, लोगों को यह सुविधा तो मुहैया हुई नहीं उल्टा क्षेत्रों में टीसीपी के नियमों को लागू कर दिया ।

अब पंचायतों के लोग इन कायदे कानून से परेशान है । लोगों को भवन निर्माण के लिए टीसीपी से नक्शे पास कराने पड़ रहे हैं । अगर निर्माण उपर नीचे होता है तो लोगों को बिजली पानी नहीं दिया जा रहा है ।

2018— कुछ यादें हि.प्र. विश्वविद्यालय की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

- दीक्षांत समारोह में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्र समुदाय को पढ़ाया ज्ञान का पाठ
- इस बार भी गोल्ड मैडल पाने वालों में शिखर पर रहीं बेटियां
- राष्ट्रपति के हाथों शारीरिक रुप से अक्षम छात्रों को मिली डिग्री
- विवि की ग्रेडिंग के लिए इस बार कैंपस का निरीक्षण करने आई नैक की टीम
- एससीए चुनाव बहाली को साल भर चलता रहा आंदोलन
- मई महीने में पेयजल संकट ने छात्रों को रुलाया
- ब्वायज होस्टल में राज्यपाल के समक्ष खुली सफाई व्यवस्था की पोल

मेधा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मेधा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र विद्यार्थियों को 31 जनवरी, 2019 तक आवेदन करना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को जारी आदेशों में बताया कि निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ई–मेल medhaprotsahanhp@gmail-com पर आवेदन पत्र भेजने होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश सरकार मेधावी विद्यार्थियों को एक लाख रुपये की मदद देगी । मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत स्कूल और कॉलेजों के 350 और विश्वविद्यालय के 150 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा । सालाना 2.50 लाख आय वाले परिवारों के विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत जमा दो के विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एफएमसी, एनडीए, सीएलएटी में प्रवेश के लिए राज्य और राज्य से बाहर के संस्थानों में कोचिंग दिलाई जाएगी । कॉलेज स्टूडेंट्स को रोजगार आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेलवे क्षेत्र में नौकरी के लिए कोचिंग दिलाई जाएगी।

अंडर ग्रेजुएशन में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 75 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के 65 फीसदी अंक होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 50 फीसदी और आरक्षित वर्ग के 45 फीसदी अंक होने चाहिए। पांच करोड़ के बजट प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना को शुरू करने की अपने पहले बजट भाषण में घोषणा की थी।

कर्ज माफी बीमारी का सही इलाज नहीं: शांता कुमार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद शांता कुमार का कहना है कि कर्ज माफी बीमारी का उचित इलाज नहीं है। बल्कि यह भविष्य में गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। इससे देश की आर्थिकी को गहरा धक्का लगता है। किसानों को राहत प्रदान करने को कर्ज माफी का प्रयोग पहले भी देश में किया गया है। लेकिन, किसानों की अर्थव्यवस्था में कोई अंतर नहीं आया है। किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला जारी रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को नकद आय प्रदान करने के निर्णय पर विचार करने को सराहनीय कदम बताया है। वर्ष 2014 में भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की ओर से भी किसानों को नकद आय सहायता देने का सुझाव दिया गया था। शांता की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने किसानों की समस्याओं पर गहन विचार किया था। विश्व के अधिकतर देशों में सरकारें किसानों को सीधे नकद सहायता प्रदान करती हैं। चीन में खाद अनुदान के रूप में 17 बिलियन डॉलर दिया जाता था। अब वहां यह पूरा धन सीधे किसानों को नकद सहायता के रूप में दिया जाता है। शांता ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों को नकद आय सहायता नहीं देना तर्कसंगत नहीं। भारत सरकार खाद अनुदान के लिए हर साल करीब 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। लेकिन, इस अनुदान का लाभ बड़ी–बड़ी खाद कंपनियों को ही मिलता है। यह राशि देश के किसानों को नकद आय सहायता के रूप में दी जाए, तो किसान अपनी इच्छा से इसका प्रयोग कर सकते हैं।

हिमाचल के सभी अस्पतालों में 56 तरह के ये टेस्ट होंगे नि:शुल्क

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नए साल से हिमाचल के अस्पतालों में अब 56 तरह के टेस्ट निःशुल्क होंगे। प्रदेश सरकार हिमाचल में फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस योजना शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जनवरी माह में इस योजना का शुभारंभ करवाने जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, किडनी, लीवर, शुगर आदि से लेकर खून की जांच से संबंधित सभी टेस्ट इस योजना के तहत निःशुल्क होंगे।

अभी ये टेस्ट कराने में मरीजों को 10 से लेकर दो हजार रुपये की राशि चुकानी पड़ती है । इसका फायदा सभी तरह के मरीजों को मिलेगा । अभी अस्पतालों में बीपीएल और आईआरडीपी मरीजों को निःशुल्क टेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी ।

विधायकों को 11 महीने के अंदर तैयार करनी होगी डीपीआर: जयराम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कहा कि यह तय किया जाएगा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) निर्धारित समय–सीमा के भीतर तैयार की जाए। नया वित्त वर्ष शुरू होने के बाद ये 11 महीनों के भीतर तैयार करनी होगी ।

उन्होंने कहा कि एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने अगले वर्ष के लिए योजना शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि एक वर्ष की यह यात्रा शानदार रही, जिसमें सरकार ने कुछ प्रमुख कल्याणकारी कदम उठाए गए।

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा का 'स्वर्णिम दृष्टिपत्र' राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए संसाधन सृजित करने को सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुछ विकासात्मक परियोजनाएं तैयार की हैं और राज्य के लिए 9,689 करोड़ की परियोजनाएं प्राप्त करने में सफल रही है।

बेल्जियम ने हॉकी विश्व कप 2018 के फाइनल में रचा इतिहास

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेल्जियम ने शूटआउट में नीदरलैंड को 3–2 से हराकर हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया।

बेल्जियम और नीदरलैंड के चारों क्वार्टर का खेल गोलरहित रहा। इसके बाद मुकाबला शूटआउट में गया, जहां बेल्जियम ने नीदरलैंड को 3–2 से हराकर जीत दर्ज की। बेल्जियम की हॉकी टीम विश्व चैंपियन बना और नीदरलैंड की हॉकी टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला।

पहली बार बेल्जियम की टीम फाइनल

इस विश्व कप में पहली बार बेल्जियम की टीम फाइनल में पहुंची थी और उसका सामना तीन बार विश्व चैंपियन रह चुकी नीदरलैंड के साथ था। बेल्जियम की टीम ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था।

पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के मुख्य बातें

पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के के लिए ओल्ली नामक कछुए को शुभंकर बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है।

हॉकी विश्व कप 2018 का एंथम सोंग को ए. आर. रहमान द्वारा तैयार किया गया था। इस एंथम सोंग के लिरिक्स "जय हिन्द, जय इंडिया" हैं। यह लिरिक्स गुलज़ार द्वारा लिखे गये हैं।

मैन ऑफ द मैच:

इस मैच में बेल्जियम के गोलकीपर विसेंट वनाश को उनके बेहतरीन खेल के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, भारत के मनप्रीत सिंह को बेस्ट सेलिब्रेशन अवार्ड से नवाजा गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्थर वन डोरेन को चुना गया। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड नीदरलैंड के गोलकीपर पिरमिन बलाक को मिला। इसके अलावा गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट बेल्जियम के हैंड्रिक्स और ऑस्ट्रेलिया के बलाक गोवर्स को दिया गया।

विश्व कप हॉकी:

विश्व कप हॉकी की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी और अभी तक पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चार बार खिताब पर कब्ज़ा किया है। ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स ने तीन–तीन और जर्मनी ने दो बार विश्व कप पर कब्ज़ा किया है। भारत ने वर्ष 1975 में विश्व कप पर कब्ज़ा किया था।

भारत में तीसरी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन

भारत में तीसरी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ। इससे पहले वर्ष 1982 और वर्ष 2010 में भारत हॉकी विश्व कप का आयोजन कर चुका है।

पुरुष हॉकी विश्व कप 2018:

पुरुष हॉकी विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में 28 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2018 के बीच किया गया। इस हॉकी विश्व कप में 16 देशों ने हिस्सा लिया था. इस विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया। इस पुरुष हॉकी विश्व कप में भाग लेने वाले टीम भारत, इंग्लैंड, मलेशिया, कनाडा, पाकिस्तान, चीन, बेल्जियम, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका थे।

पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, वर्ल्ड टूर ख़िताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। सिंधु यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं हैं।

सिंधु ने यह मुकाबला 62 मिनट में 21–19, 21–17 से अपने नाम किया। इस साल सिंधु का यह पहला खिताब है। इससे पहले 2018 में उन्हें विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, थाईलैंड ओपन और इंडिया ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

वर्ल्ड रैंकिंग में सिंधु

टूर्नामेंट में जीत के बाद सिंधु ने रैंकिंग्स के शिखर तक पहुंचने की ओर लंबी छलांग लगा दी है। वर्तमान में वे दुनिया में नंबर 6 पर काबिज हैं। सिंधु के खाते में कुल 81,614 पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने पर सिंधु को 12 हजार पॉइंट्स मिले हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग्स अपडेट होने पर वह 93,614 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगी। वर्ल्ड नंबर वन ताइ जू टॉप पर बनीं रहेंगी।

राज्यों की स्टार्ट–अप रैंकिंग 2018 घोषित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 20 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट–अप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित कर दिए। यह अपने तरह की पहली रैंकिंग है। डीआईपीपी ने इसकी कवायद जनवरी 2016 से शुरू कर दी थी औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उभरते उद्यमियों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित कराने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर रहा है।

लोकसभा चुनाव 2019: निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार के तंबाकू पर रोक लगायी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सभी मतदान स्थलों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने यह मुहिम देश में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए शुरू की है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा–निर्देश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों या जिला मजिस्ट्रेटों को नासिर्फ धूमपान पर पाबंदी लगाने को कहा है, बल्कि सभी मतदान स्थलों पर चबाने वाले तंबाकू पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग

भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध–न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया था।

भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बोगीबील पुल का उद्घाटन किया, जानिए क्या हैं इसकी खासियत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल/रोड ब्रिज बोगीबील का उद्घाटन किया। यह ब्रिज 4.94 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रिज भारत–चीन बॉर्डर एरिया में काफी महत्तवपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने इस पुल को मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्टिंग तथा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसी आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करके इसे यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाया है। यह पुल अरुणाचल में बॉर्डर के समीप भारत यातायात सुगम बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

इस परियोजना का शिलान्यास 22 जनवरी 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा द्वारा किया गया था। हालांकि इस पर काम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 21 अप्रैल 2002 को हुई। परियोजना में हुई देरी के कारण इसकी लागत 85 फीसदी तक बढ़ गई। इस ब्रिज के रणनीतिक महत्व को देखते हुए 2007 में इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। यह ब्रिज पूर्वी क्षेत्र में तेजी से सेना और हथियारों की आवाजाही को बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा।

सबसे लंबा रेल/रोड ब्रिज:

हालांकि बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 10.3 किलोमीटर है लेकिन रेलवे पुल बनाने के लिए यहां तकनीक लगाकर पहले नदी की चौड़ाई कम की गई और फिर इस पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल/रोड ब्रिज बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा रेल/रोड ब्रिज है।

लोकसभा में पास हुआ तीन तलाक विधेयक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा में तीन तलाक (ट्रिपल तलाक) विधेयक 27 दिसंबर 2018 को पास हो गया. इसके पक्ष में 245 वोट पड़े हैं. वहीं बिल के विरोध में 11 वोट डाले गए हैं। ट्रिपल तलाक की प्रथा को रोकने के मकसद से यह बिल लाया गया है। अब इसे राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2017 में ट्रिपल तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) की प्रथा को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को कानून बनाने को कहा था। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक लोकसभा से पारित कराया, लेकिन यह बिल राज्यसभा में अटक गया क्योंकि उच्च सदन सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इसके बाद सरकार को तीन तलाक पर अध्यादेश लाना पड़ा था। इसकी अवधि 6 महीने की होती है।

ट्रिपल तलाक देश में विवादास्पद मुद्दा रहा है। विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक आस्था का सवाल बताया तो सरकार का कहना है कि इसे प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने के मकसद से लाया गया विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों और न्याय के बारे में है। भारत से पहले दुनिया के 22 ऐसे देश हैं जहां तीन तलाक पूरी तरह प्रतिबंधित है। दुनिया का पहला देश मिस्र है जहां तीन तलाक को पहली बार बैन किया गया था।

सामान्य ज्ञान

1. वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में किस राजनेता को हाल ही में उम्रकैद की सजा सुनाई गई?
अ. जगदीश टाइटलर इ. जगदीश मुखी
ब. सज्जन कुमार क. उमेश राठौर

2. निम्नलिखित में से किसने हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की?
अ. भूपेश बघेल इ. रमेश बघेल
ब. टीएस सिंह देव क. टी.डी. साहू

3. दिल्ली एनसीआर का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है?
अ. ग्रेटर नोएडा इ. अलवर
ब. मानेसर क. कोंडली

4. अडानी समूह द्वारा संचालित भारत में पहली मानव रहित यान निर्माण फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है?
अ मैसूर इ. हैदराबाद
ब. कोच्चि क. सूरत

5. अडानी समूह ने इजराइल की किस कम्पनी के साथ मिलकर भारत में पहली यूएवी निर्माण कंपनी स्थापित की है?
अ. इनसाइट्स इ.आयरन सोर्स
ब.इजराइल केमिकल्स क.एल्बिट सिस्टम्स

6. भारतीय वायुसेना के किस विमान ने हाल ही में बायो–फ्यूल के साथ विमान की उड़ान का सफल परीक्षण किया ?
अ.एएन–32 इ. जेपीसी–22
ब.इंडियाना–12 क. द्रोण

7. भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के लिए फ्रांस की किस कम्पनी के साथ 4500 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं?
अ. मेवरिक ब्रदर्स इ. जॉन एंड जेनिस
ब. एटॉस क.क्योरोकेन

8. प्रतिवर्ष किस तारीख को अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है?
अ 15 दिसम्बर इ. 10 दिसम्बर
ब. 12 दिसम्बर क. 18 दिसम्बर

9. भारत और किस देश ने 17 दिसंबर 2018 को हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है?
अ नेपाल इ. चीन
ब. मालदीव क. रूस

10. केंद्र सरकार ने सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिये किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी?
अ. उज्ज्वला योजना
इ. प्रधानमंत्री जनधन योजना
ब. प्रधानमंत्री जीवन ज्योनति बीमा योजना
क. राष्ट्रीय व स्वास्थ्य बीमा योजना

11. आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु के समानांतर एक नये 5.634 किलोमीटर लंबे कितने लेन के पुल के निर्माण को मंजूरी दी है?
अ 2 लेन इ. 4 लेन
ब. 6 लेन क. इनमें से कोई नहीं

12. भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 'इंद्र नौसेना' युद्ध अभ्यास का 10वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में समाप्त हुआ ?
अ रूस इ. नेपाल
ब. चीन क. जापान

उत्तर:

1. ब. सज्जन कुमार : वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिख पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया ।

2. अ भूपेश बघेल : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली ।

3. अ ग्रेटर नोएडा : एनसीआर की बढ़ती आबादी को विश्व स्तरीय परिवहन सुविधा मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) के निर्माण को मंजूरी दी है।

4. इ. हैदराबाद : अडानी समूह तथा इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से भारत की पहली निजी मानव रहित विमान (यूएवी) निर्माण फैक्ट्री हैदराबाद में आरंभ की गई है ।

5. क. एल्बिट सिस्टम्स : अडानी समूह तथा इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से भारत की पहली निजी मानव रहित विमान (यूएवी) निर्माण फैक्ट्री हैदराबाद में आरंभ की गई है । यह देश में इस प्रकार की पहली यूनिट है ।

6. अ एएन–32 : भारतीय वायुसेना के प्रमुख परीक्षण स्थल एएसटीई, बंगलुरु में पायलटों और इंजीनियरों ने एएन–32 सैनिक परिवहन विमान में पहली बार मिश्रित बायो जेट ईंधन का इस्तेमाल करते हुए प्रायोगिक उड़ान भरी।

7. ब. एटॉस : भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के लिए फ्रांस की कंपनी एटॉस के साथ 4500 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं । इस समझौते का उद्देश्य 70 से अधिक सुपरकंप्यूटर तैयार करना है ।

8. क. 18 दिसम्बर : दुनियाभर में 18 दिसंबर 2018 को 'अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस' मनाया गया । वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का विषय–सम्मान के साथ प्रवास (Migration with Dignity) है ।

9. ब. मालदीव : भारत और मालदीव ने 17 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है ।

10. अ उज्ज्वला योजना: केंद्र सरकार ने सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिये उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दी । इस योजना को 2016 में शुरू किया गया ।

11. इ. 4 लेन : आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु के समानांतर एक नये 5.634 किलोमीटर लंबे 4 लेन के पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है ।

12. अ. रूस : भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच 'इंद्र नौसेना' युद्ध अभ्यास का 10वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में समाप्त हुआ । इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच इंटरओपेराबिलिटी को बढ़ावा देना है ।

दुनिया में 'इबोला' का कहर, शवयात्रा में शामिल लोगों को भी ले सकता है चपेट में

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इबोला का नाम सुनते ही दुनिया के कई मुल्कों के कान खड़े हो जाते हैं। कई अफ्रीकी मुल्कों में यह वायरस कहर बनकर टूटा है। अब भी यहां के कई मुल्क इसकी चपेट में हैं। यह एक ऐसा खतरनाक वायरस है कि संक्रमित शव के साथ चल रहे लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इबोला के शिकार व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी खतरे से खाली नहीं होता। शव को छूने से भी इसका संक्रमण हो सकता है। दरअसल, इन दिनों अफ्रीका के कई मुल्क दो तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले, तो गृहयुद्ध से निपटने में उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। दूसरी ओर इबोला वायरस ने देश में अपना तांडव मचा रखा है । यहां सबसे बड़ी मुश्किल यह आ रही है कि विद्रोहियों के चलते वायरल की चपेट में आए रोगियों को मदद नहीं मिल पा रही है । इसमें एक प्रमुख राष्ट्र कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है । यहां राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए स्थितियां और जटिल हो गई हैं। यहां अब तक इस वायरल की चपेट में आकर 319 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगो सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि यह वायरस यहां करीब चार महीने तक और सक्रिय रहेगा। क्रिसमस को देखते हुए आंशका जाहिर की जा रही है कि यह दुनिया के अन्य मुल्कों में भी फैल सकता है। इसके मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लोगों को आगाह किया है ।

पाकिस्तान ने भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को रिहा किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान ने भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को सोमवार को रिहा कर दिया जिसकी तीन साल की सजा पूरी हो गई थी। इससे पहले एक शीर्ष अदालत ने सरकार को उसे वापस भेजे जाने की औपचारिकताएं एक महीने के भीतर पूरी कर लेने को कहा था । पाक की खुफिया एजेंसी ने अंसारी को 2012 में पकड़ा था और 2015 में एक सैन्य अदालत ने उसे फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी । 15 दिसंबर 2015 को सजा सुनाए जाने के बाद से 33 वर्षीय मुंबई निवासी अंसारी पेशावर केंद्रीय कारागार में बंद था । उसकी तीन साल की सजा 15 दिसंबर, 2018 को पूरी हो गई थी लेकिन कानूनी दस्तावेज तैयार नहीं होने की वजह से वह भारत रवाना नहीं हो पा रहा था । बृहस्पतिवार को पेशावर उच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को एक महीने के भीतर उसको स्वदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था । विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा 'अंसारी को उसकी सजा पूरी होने के बाद रिहा किया गया और भारत भेजा रहा है।' उन्होंने दावा किया कि अंसारी एक 'भारतीय जासूस था जिसने अवैध तरीके से पाकिस्तान में प्रवेश किया था और वह राष्ट्र विरोधी अपराधों एवं फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल था ।' पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों एवं कोहाट की स्थानीय पुलिस द्वारा 2012 में हिरासत में लिए जाने के बाद से अंसारी लापता हो गया था और आखिरकार उसकी मां फौजिया अंसारी द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि वह पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हैं और एक सैन्य अदालत में उसपर मुकदमा चलाया जा रहा है । खबरों के मुताबिक ऑनलाइन चटिंग चैटिंग के दौरान एक लड़की से दोस्ती के बाद उससे मिलने की चाहत में वह अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया था। पेशावर उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने अंसारी के वकील काजी मुहम्मद अनवर के जरिए उसकी ओर से दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की। इस पीठ में न्यायमूर्ति रूहुल अमीन और न्यायमूर्ति कलंदर अली खान शामिल थे। अनवर ने पीठ को सूचित किया कि गृह मंत्रालय एवं जेल अधिकारियों ने उसकी रिहाई एवं भारत वापसी पर पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है जिसके बाद न्यायमूर्ति खान ने अतिरिक्त एटॉर्नी जनरल से यह बताने को कहा था कि सजा पूरी होने के बाद वे किसी कैदी को जेल में कैसे रख सकते हैं । गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाने की सूरत में एक कैदी को एक महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है । कानूनी स्थिति जानने के बाद अदालत ने एक महीने के भीतर औपचारिकता पूरी करने का निर्देश दिया ।

चीन के शिंजियांग प्रांत से क्यों गायब हो रहीं उइगर मुस्लिमों की बीवियां

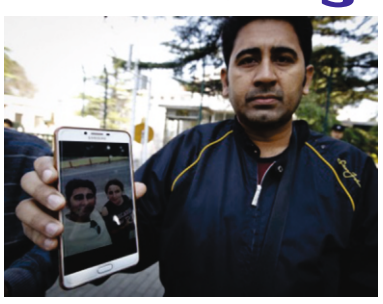

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन के शिंजियांग प्रांत से 200 से अधिक मुस्लिम व्यापारियों की पत्नियां लापता हो गई हैं । जब उन्होंने इस संबंध में शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नियों को 'शैक्षणिक केंद्र' ले जाया गया है । चौधरी जावेद अट्टा भी उन्हीं में से हैं और उनकी पत्नी एक साल पहले लापता हो गई हैं । उन्हें अपने वीजा को रिन्यू कराने के लिए दोबारा पाकिस्तान आना पड़ा है और वहां से आने के बाद वह अपनी की तलाश फिर शुरू करेंगे । अट्टा ने कहा कि उनकी पत्नी ने आखिरी बार उनसे कहा था, 'जैसे ही आप जाएंगे, वे मुझे कैंप में ले जाएंगे और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी ।' जब दोनों अलग हुए थे उस वक्त उइगर मुस्लिम अट्टा और अमीना मानजी की शादी को 14 साल हो गए थे। अमीना अगस्त 2017 से लापता है । अट्टा ने बताया कि शिंजियांग में 200 से अधिक पाक व्यापारियों की पत्नियां लापता हैं । जब वे अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो चीनी अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शैक्षणिक केंद्र ले जाया गया है । चीन पर ये आरोप लगते हैं कि उसने उइगरों को नजरबंद कर रखा है और उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं से दूर कर री–एजुकेट किया जा रहा है । माना जा रहा है कि हिंसा और दंगे को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। अट्टा बताते हैं, 'वे उसे स्कूल बताते हैं, जबकि वह जेल है ।'

ये टॉप–6 हथियार महासंग्राम में रूस को बनाते हैं अजेय ! चौंका अमेरिका

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान से इस बात की आशंका प्रबल हो गई है कि दुनिया में शांत हो चुके शीत युद्ध की चिंगारी दोबारा सुलग सकती है। रूसी राष्ट्रपति के एक बयान से अमेरिकी प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया, जिससे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चौंकन्ना हो गया । आइए जानते हैं पुतिन के इस कथन के पीछे का पूरा सच और उनके बयान की सच्चाई। दरअसल, मार्च में राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्र के संबोधन के दौरान अपने हाइपर्सोनिक शस्त्रागार को 'अजेय' बताया था । हाल में मॉस्को में सैन्य प्रमुखों के साथ बैठक में पुतिन ने रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क के रूप में घोषित किया। उनकी यह धारणा अजेय रूस से मेल खाती है । राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी बात को यही विराम नहीं दिया । उन्होंने अपने मुल्कों के उन अत्याधुनिक हथियारों से से भी पर्दा उठा दिया, जिसकी अमेरिका समेत दुनिया में किसी मुल्क के पास कोई काट नहीं है । दरअसल, सैन्य सम्मेलन में पुतिन का यह उत्साही बयान रूस के लिए नया संकट खड़ा कर सकता है । अमेरिका ने पुतिन के इस बयान को गंभीरता से लिया है । उसने पुतिन के बयान के हवाले से कहा है कि रूस ने 1987 इंटरमीडिएट–रेंज परमाणु संधि का उल्लंघन किया है । बता दें कि 1987 में हुई अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत अमरीका और सोवियत संघ को 500 से पांच हजार किलोमीटर तक की मार करने वाले परमाणु हथियार को नष्ट करना था । इस करार पर सोवियत संघ राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने हस्ताक्षर किए थे । उधर, रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी आरोपों का सिरे से खंडन किया है ।

करतारपुर के संबंध में पाकिस्तान ने भारत के 'इस' प्रस्ताव को ठुकराया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत और पाकिस्तान के बीच जब रिश्ते सामान्य होते हैं, तब भी भारत द्वारा दिए गए अच्छे प्रस्तावों को पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता । फिलहाल तो दोनों देशों के रिश्तों में धूल जमी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान से किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने की उम्मीद भी बेमानी सी लगती है ।

बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें नई दिल्ली ने कहा था कि इस्लामाबाद करतारपुर भारत को दे दे और उसके बदले वह दूसरी जमीन ले ले । यह प्रस्ताव करतारपुर को भारत का हिस्सा बनाने के मकसद से दिया गया था ।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने इस्लामाबाद में कहा, 'जमीन अदला–बदली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ।' उनसे पूछा गया था कि क्या उनका देश अदला–बदली सौदे के तहत करतारपुर की जमीन भारत को सुपुर्द करने पर विचार करेगा ?

संयुक्त राष्ट्र में फांसी पर रोक के प्रस्ताव पर वोट को गलत तरीके से गिना गया :पाक एफओ

मौत की सजा पर वोट को गलत तरह से गिना गया: पाक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में फांसी की सजा पर रोक की मांग करने वाले एक प्रस्ताव पर उसके वोट को गलत तरीके से प्रस्ताव के पक्ष में गिना गया । विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने सोमवार के मतदान के बारे में स्पष्टीकरण दिया जो खबरों के अनुसार महासभा के प्रस्ताव के समर्थन में चला गया। फैसल ने एक ट्वीट में कहा, 'पाकिस्तान ने अपनी सतत नीति के अनुसार मृत्युदंड को खत्म करने के विचार के साथ फांसी पर रोक का आह्वान करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था ।' एमनेस्टी इंटरनैशनल ने सोमवार को रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान सहित संयुक्त राष्ट्र के चार सदस्य देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में अपना वोट बदल दिया । अन्य तीन देश डोमिनिका, लीबिया और मलेशिया है । संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से कुल 121 ने मौत की सजा के इस्तेमाल पर रोक के आह्वान वाले सातवें प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था । अन्य 35 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था जबकि 32 सदस्य अनुपस्थित रहे थे ।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादक: आनन्द नायर फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com

RNI Reference No. 1328500

सामान्य ज्ञान

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सीपीजे) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में (1 दिसंबर तक) दुनियाभर में इतने पत्रकार जेलों में बंद किए गए

उत्तर: 251

- रेलवे द्वारा जनवरी 2019 में प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले के लिए 700 करोड़ रुपये राशि से आरंभ की गई योजनाओं की संख्या है

उत्तर : 41

- वह राज्य जिसके हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा है कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था इसलिए उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था

उत्तर : मेघालय

- टीवीएस मोटर के चेयरमैन जिन्हें हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने वाइस–चेयरमैन नियुक्त किया है

उत्तर: वेणु श्रीनिवासन

- वह बैंक जिसने 31 दिसंबर तक देशभर में 40 नई शाखाएं खोलने की घोषणा की है जिससे उसकी कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर 978 हो जाएगी

उत्तर : बंधन बैंक

- ऑस्ट्रेलिया की 102 वर्षीय महिला का जो स्काईडाइविंग करने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बनीं हैं

उत्तर – अरीन ओशे

- विश्व के इस भाग में वर्ष 2014–18 के दौरान कुल 28,523 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है

उत्तर : खाड़ी देश

- इन्होने हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है

उत्तर : के. चंद्रशेखर राव

- इन्हें हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द इयर 2018 चुना गया है

उत्तर : जमाल खाशोगी

- नासा के अंतरिक्ष यान का नाम जिसने हाल ही में सौरमंडल के छोर तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया

उत्तर – वॉएजर–2

भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर जिसे नियुक्त किया गया है उत्तर : शक्तिकांत दास

- केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ जितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये–

उत्तर : 31 मिलियन डॉलर

- वह क्रिकेटर जिसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया–

उत्तर :अजय रोहेरा

- हाल ही में जिस भारतीय शहर में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया–

उत्तर : मोहाली

- जिस शहर में खेलो इंडिया युवा खेल–2019 आयोजित किया जाएगा–

उत्तर : पुणे

- तेलंगाना विधानसभा चुनाव के घोषित नतीजों में टीआरएस नेता टी. हरीश राव ने सिद्दीपेट विधानसभा सीट से एक लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर लगातार जितनी बार जीत दर्ज की है–

उत्तर : छठी बार

- ग्लोबल कार्बन परियोजना के अनुसार, विश्व कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जितने प्रतिशत तक बढ़ गया है–

उत्तर : 2.7 प्रतिशत

- ऑहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के जिस प्रोफेसर ने ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2018 को जीता–

उत्तर : रतन लाल

- भारत के जिस नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है–

उत्तर : राजीव महर्षि

- हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने जितने किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकाप्टर का विकास किया–

उत्तर : 6 किलोमीटर

ग्रामीणों ने कहा धन्यवाद, 'मिशन रीव'

पागल कुत्ते द्वारा काटी गई गाय के दूध से था रोग फैलने का खतरा

प्रशासन और विभाग ने भी की सराहना

रीव जागरूकता अभियान से टला था रेबीज का बड़ा संकट

द रीव टाइम्स www.therievtimes.com गांव की समस्याएं 16-31 अक्तूबर, 2018 13

चंबा के रजेरा के अंतर्गत थला गांव में पागल कुत्ते के काटने से गाय की मौत

परिवार पीता रहा दूध और गांव के श्राद्ध में उसी दूध से बनी छाछ को पीते रहे लोग : फिर गाय की मौत पर हुआ खुलासा

मिशन रीव ने सबसे पहले इस मुद्दे पर प्रशासन और गांव में की जागरूकता

द रीव टाइम्स चम्बा (हम राज चौहान) प्रदेश के जिला चंबा के रजेरा डाकखाना के तहत गांव थला में एक आवारा पागल कुत्ते ने जंगल में चर रही गाय को काट दिया। उस गाय को कुत्ते द्वारा काटे जाने की घटना को जीरो

गंभीरता से न लेते हुए उस परिवार ने दूध आदि का सेवन स्वयं तो किया ही... पूरे गांव को श्राद्ध में उसी गाय के दूध से बनी लस्सी लोगों को पिलाते रहे और उसी लस्सी से लोगों के लिए पास में बड़ी बनाई एवं खिलाई गयी। उसी गाय ने एक जागरण में गणपति मंदिर में भण्डारा का आयोजन भी किया गया था जिसमें उसी गाय के दूध एवं लस्सी/छाछ का उपयोग किया गया। अनजाने हुए इस लापरवाह प्रकरण का तब पता चला जब गाय पागल होकर मर गई। पूरे गांव में अफरा-तफरी हो गई। लस्सी को मालूम ही नहीं हो रहा था कि श्राद्ध में उस गाय के दूध और छाछ के उपयोग के बाद उन्हें अब क्या करना है। प्रभावित परिवार के मुखिया – सुखी राम ने बताया कि उनकी गाय को कुत्ते ने काटा था और इसके बाद पूरे परिवार ने उसका दूध पीया और दूध के अन्य उत्पाद भी उपयोग में लाए। इसलिए सारा परिवार टीके लगवा रहा है। उनके अन्य मवेशियों को भी टीकाकरण करवाया गया है।

मिशन रीव ने लिया संज्ञान

गाय के पागल होने तथा मर जाने के बाद कुछ लोगों ने तो रेफिडालान डॉक्टर को संपर्क कर टीका लगा लिया लेकिन कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। खास तक कि अज्ञानतावश कुछ ने ये भी कहा कि कुत्ते के उपचार में सब रोकेट खत्म हो गए हैं। इसलिए टीके लगवाने की आवश्यकता ही नहीं है। मिशन रीव ने इस पर चिंता संज्ञान लेते हुए प्रशासन को इस घटना की गंभीरता से लेने तथा आवश्यक कदम उठाने के लिए पत्राचार एवं बैठक की। मिशन रीव की ओर से रीव जिला समन्वयक राकेश शर्मा ने उपायुक्त चंबा... से मिलकर इस समस्या पर तुरंत ठोस कदम उठाने की प्रार्थना की। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा से भी मुलाकात कर लोगों को तुरंत आवश्यक टीके लगाने के लिए पत्राचार किया।

सीएमओ चंबा पाई डी शर्मा

मिशन रीव जिला समन्वयक राकेश शर्मा एवं अतिरिक्त जिला समन्वयक विकास शर्मा ने इस समस्या को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाया। इसके अलावा प्रभावित गांवों का स्वयं भ्रमण कर न केवल वास्तविक स्थिति से जानकर हुए अपितु ग्रामीणों को जागरूक भी किया।

क्या कहती है बी एम ओ डॉ पदमा

बी एम ओ डॉ. पदमा ने भी इस विषय को लेकर सावधान की गई। डॉ. पदमा ने बताया कि कच्चे दूध अथवा लस्सी का सेवन करने की स्थिति में खतरा बढ़ जाता है लेकिन कढ़ी में इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जबकि रीव चिकित्सक ने डॉ. के साथ शामिल करते हैं कि यह खतरा कढ़ी में भी पलता है। जिसके कच्चे दूध अथवा लस्सी के सीधे सेवन से है क्योंकि स्थिति का वास्तव आसानी से खत्म नहीं होता। यह 14 वर्षों बाद भी शरीर में असर दिखा देता है।

क्या कहा आईजीएमसी डॉ प्रवीण भाटिया ने

हरिश्री सोती मेडिकल कॉलेज जिलाला के डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने इस बात बताया कि प्रभावित/मृत गाय के दूध अथवा लस्सी का सेवन बिना-बिना लोगों ने किया उन्हें तुरंत टीके लगाने की आवश्यकता है। हालांकि लस्सी के कढ़ी में पक जाने के बाद खतरा कम हो जाता है फिर भी रेफिडालान टीके लगवा लेने चाहिए। साथ ही पशुओं का पंजीकरण भी करवा लिया जाना चाहिए क्योंकि मृत गाय ने जहां पानी पीया था उसी स्थिर जल को गांव के अन्य पशुओं ने भी पीया था।

पशु डिसपेंसरी के कार्यालिस्ट के अनुसार :

पशु डिसपेंसरी के कार्यालिस्ट सुरेश ठाकुर ने बताया कि प्रभावित परिवार के अन्य मवेशियों को भी टीकाकरण किया जा चुका है तथा लोगों को जागरूक किया गया है।

एफ एच इन्स्पू ने कहा :

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता धनदेवी से बात करने पर पता चला कि लोग इस घटना से सामने तो हैं किंतु यदि उनके लिए सही प्रकार से जानकारी और उपचार मिल जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थिति यदि आवश्यक टीकों की व्यवस्था एवं शिविर में ही पाएगाम्पल पर ही कर दे तो सभी का उपचार यहीं पर सरलता से संभव हो जाएगा।

इसी के तहत चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के मिशन रीव टीम ने बैठक कर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद से ही विभाग सतर्कता के साथ मुस्तैद है तथा अवस्था इस पर नजर रखी जा रही है।

मिशन रीव ने किया प्रभावित गांवों का दौरा

मिशन रीव की टीम प्रभावित गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में लोगों को घर-घर जाकर जागरूक कर रही है। प्रभावित गांव में थला के अलावा टिक्कर, ककला और बैली है क्योंकि भण्डारे में इन गांवों के लोग भी शामिल हुए थे। टिक्कर गांव में प्रभावितों में दूसरी देवी, निक्की, गीता, नीतू देवी, काकू, अंजू, आरथी, नीनूदिष्टु, सुंदरी देवी और उनी शामिल है।

प्रभावित परिवार का घर

गांव थला से सीमा, सत्तो, रेखा, गुरुम, काजल, आदुप प्रभावितों में हैं। गांव बैली और ककला से जांबी, सुरिंदा तथा अन्य प्रभावित हैं।

घटनास्थल पर पहुंच कर मिशन रीव ने किया जागरूकता

इसके साथ ही राजेरी पंचायत के अंतर्गत संबंधित गांव थला में मिशन रीव ने एक जागरूकता बैठक भी की तथा लोगों को इस समस्या से बेरी निपटना है इस पर जागरूकता की। मिशन रीव टीम राकेश शर्मा की अध्यक्षता में वास्तविकों से मिली गांव का निरीक्षण कर लोगों से बात की। लोगों को बताया गया कि इसके लिए किसने टीके शामिल है, दो वर्षों लगाने के बाद ही इसके बचाव किया जा सकता है। इसके लिए जो लोग टीका नहीं लगवा पाए हैं उन्हें समय सीमा के अंदर ही टीका लगाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी गंभीर समस्या से नहीं जूझना पड़े।

क्या कहते हैं ग्राम पंचायत प्रधान किशन चंद

रीव टाइम्स ने स्थानीय पंचायत रजेरी प्रधान किशन चंद से बात की तो उन्होंने इस बात से स्वीकार किया कि उनकी पंचायत के गांव थला में वे घटना हुई है और इससे पूरे गांव के अलावा बाहरी लोग यदि जागरूक में और भण्डारे में शामिल हुए थे प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गाय को पागल कुत्ते ने काटा था और उस गाय की कुछ दिन बाद मौत हो गई। लेकिन परिवार के अलावा गांव में बाद में उसी गाय के दूध और छाछ का उपयोग होता रहा। साथ ही एक जागरण में करवे दिन भण्डारे में उसी गाय के दूध और छाछ का उपयोग हुआ था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से बात कर इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की थी। अस्पताल में स्वयं को टीका लगा लिया है तथा कुछ लोग अभी भी शेष बचे हैं। जिन्हें शीघ्र ही इसके लिए ले जाया जाएगा। उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि मिशन रीव की पहल सराहनीय है और इस प्रकार की जागरूकता के लिए वो रीव का आभार जताते हैं।

इस घटना पर रीव क्लिनिक के डॉक्टर के आर शाडिल क्या कहते हैं

हमने बात की रीव क्लिनिक के डॉक्टर के आर शाडिल से तो उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है और यदि इस प्रकार की घटना हो जाए तो तुरंत समयसीमा के अंदर इसके लिए रेबिज के इंजेक्शन लगवाने चाहते हैं। इस टीका का नाम रेबिपूर होता है तथा इसका लगना अति आवश्यक होता है। रेबिपूर के पांच टीके (0/03/07/14/28) लगते हैं जिसके अवधान में निशुल्क लगाया जाता है। यदि इसे नहीं लगाया जाता और वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है और उसके बाद तीवर, किडनी एवं अन्य आंगनन में प्रवेश कर शार्ट सेल कर देता है। इसके लक्षण 14 वर्ष के बाद भी दिखाई देते हैं क्योंकि यह एक बेहद खतरनाक वायरस है जो आसानी से नहीं मरता। इसके लिए बराए गए टीके लगने से ही सुरक्षा की गारंटी होती है।

डरे-सहमे हैं लोग अन्य पशुओं और कुत्तों में भी हो सकता है खतरा

द रीव टाइम्स के साथ स्थानीय लोगों ने बातचीत की व इस घटना के बाद से बहुत डरे-सहमे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि यहां एक खास/पालतू पशुओं के पानी पीने का स्थान है जहां पागल कुत्ते द्वारा काटी गई गाय ने पानी पीया तथा उसके बाद गांव के सभी पशुओं ने भी इसमें लगातार पानी पीया इससे उस गाय की लार से स्पर्शित जल सभी पशुओं के पीने के बाद खतरा हो सकता है। साथ ही गांव के कुत्तों से भी डर बन गया है और लोगों ने कुत्तों को सावधिक रूप से मारने की बात की जाही।

इसका असर यह है कि लोग कुत्तों को मारने लग पड़े हैं। कुत्तों ने तो प्रशासन से गांव की कि उनके जो लोग टीका लगवाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए गांव में ही प्रबन्ध हो तथा सभी पशुओं को एक शिविर लगाकर पशु चिकित्सालय के डॉक्टर की टीम वैक्स कर आवश्यक कार्यवाही करें।

मिशन रीव की इस बाबत पहल

मिशन रीव ने इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत रजेरा के प्रधान के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों के हस्ताक्षर सहित रीव के प्रार्थना पत्र पर पशु चिकित्सालय ने प्रार्थना की है कि अतिशीघ्र गांव में पूरी टीम के साथ पशुओं का वैक्सन और उपचार के लिए सेवाएं दें। इसके मिशन रीव की टीम भी साथ होगी और पूरा सहयोग करेगी।

टीम रीव, चम्बा

तीन माह पूर्व चंबा के दूरदराज गांव थला के लोग उस समय सहम गए थे जब उन्हें पता चला कि गांव पर रेबीज का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन संकट की उस घड़ी से निपटने में मिशन रीव ने जो योगदान दिया उसकी सराहना आज भी थला गांव के लोग खुले मन से करते हैं।

दरअसल, अक्तूबर माह में थला समेत आसपास के गांव में रेबीज प्रभावित एक गाय के दूध से बनी कढ़ी और छाछ के सेवन से रेबीज फैलने का खतरा पैदा हो गया था। इस संभावित खतरे और उसे निपटने के लिए मिशन रीव ने जागरूकता अभियान चलाया था। अब तीन माह बाद एक बाद फिर गांव के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मिशन रीव की टीम ने जिला संयोजक राकेश शर्मा की अगुवाई में उस समय के प्रभावित गांवों का दौरा किया और लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

थला गांव से सीमा, सत्तो, रेखा, काजल व अन्य प्रभावितों ने कहा,

हम तो भोजन करने के बाद घर आ गए थे। कोई सूचना ही नहीं थी कि श्राद्ध में जिस गाय के दूध का इस्तेमाल कढ़ी बनाने और छाछ के लिए किया गया उसको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। वह तो धन्यवाद है मिशन रीव प्रतिनिधियों का कि समय रहते उन्होंने हमें यह बताया और बाकि आसपास के गांव के लोगों को भी जागरूक किया'।

मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया। थला के अलावा बैली, ककला और टिक्कर जाकर भी मिशन रीव की टीम ने लोगों को समय रहते रेबीज के लक्षणों और इसके बचाव के लिए टीकारण के लिए प्रेरित किया।

हालांकि मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी संज्ञान लिया गया लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो श्राद्ध खाने के बाद अपने–अपने गांव चले गए और उन्हें रेबीज के संभावित खतरे के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए वह टीकारण को लेकर भी गंभीर नहीं थे। मिशन रीव की टीम ने इन्हीं गांवों में ढाई से तीन घंटे का पैदल रास्ता तय कर लोगों के घर जाकर उनसे बात की और टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया।

आज इन गांवों के लोग मिशन रीव की इसी पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मिशन रीव की टीम ने जिस तरह से उस समय रेबीज के खतरे से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया वह क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आसान नहीं था लेकिन मिशन रीव ने यह कर दिखाया और आज गांव के सभी लोग स्वस्थ्य है।

क्या था मामला

चंबा के रजेरा डाकखाने के तहत थला गांव में एक पागल कुत्ते ने जंगल में चर रही गाय को काट दिया। उस समय किसी ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच गाय के मालिक के घर में श्राद्ध का आयोजन हुआ और उसमें इसी गाय के दूध से कढ़ी बनाई गई और छाछ तैयार की गई। श्राद्ध में आए गांव के लोगों ने इसका सेवन किया। इतना ही नहीं गांव में ही गणपति मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी इसी गाय के दूध का इस्तेमाल हुआ।

दोनों ही आयोजनों में आए लोगों ने कढ़ी और छाछ का सेवन किया। लेकिन गांव में उस समय अफरा–तफरी मच गई जब श्राद्ध और मंदिर में हुए आयोजन के बाद गाय पागल होकर मर गई।

कुछ जागरूक लोगों ने तो टीककरण करवा लिया लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो टीकाकरण जरूरी नहीं समझ रहे थे। इसी का संज्ञान लेते हुए मिशन रीव की टीम ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और रेबीज के खतरे से निपटने के लिए टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसी का नतीजा रहा कि लोगों ने समय रहते टीकारण करवाया और आज सभी खतरे से बाहर हैं।

रेबीज और क्या हैं इसके लक्षण और बचाव

रेबीज एक तरह का वायरल इंफेक्शन है, जो जानवरों के काटने से फैलता है। रेबीज के वायरस व्यक्ति के नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं और पागल बना देते हैं।

जानवरों के चाटने से भी फैल सकता है रेबीज का वायरस

रेबीज एक ऐसा वायरस है, जो आमतौर पर जानवरों के काटने से फैलता है। ये एक जानलेवा रोग है क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर में दिखने शुरू होते हैं। इसी कारण जब किसी व्यक्ति में रेबीज के वायरस होते हैं, तो लक्षण दिखने तक इलाज का समय आमतौर पर निकल चुका होता है। रेबीज खतरनाक है मगर इसके बारे में लोगों की कम जानकारी और ज्यादा घातक साबित होती है।

आमतौर पर लोग मानते हैं कि रेबीज केवल कुत्तों के काटने से होता है मगर ऐसा नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि कई जानवरों के काटने से इस बीमारी के वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा कई बार पालतू जानवर के चाटने या खून का जानवर के लार से सीधे संपर्क से भी ये रोग फैलता है। आइए आपको बताते हैं किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है रेबीज और क्या हैं इसके लक्षण और उपचार।

कैसे प्रभावित करता है रेबीज

रेबीज एक तरह का वायरल इंफेक्शन है, जो आतमौर पर संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है। ये वायरस खतरनाक होता है और अगर समय से इलाज न किया जाए, जो ज्यादातर जानलेवा साबित होता है। रेबीज वायरस किसी व्यक्ति के शरीर को दो तरह से प्रभावित करता है।

जब रेबीज वायरस सीधे व्यक्ति के नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंच जाए।

जब रेबीज वायरस मसल टिशूज (मांसपेशीय ऊतकों) में पहुंच जाते हैं, जहां वो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) से बचे रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद ये वायरस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के द्वारा नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं।

रेबीज वायरस जब व्यक्ति के नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं, तो ये दिमाग में सूजन पैदा कर देते हैं, जिससे जल्द ही व्यक्ति कोमा में चला जाता है या उसकी मौत हो जाती है। इस रोग के कारण कई बार व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वो बिना बात उत्तेजित हो जाता है और कई बार उसे पानी से डर लगने लगता है। इसके अलावा कुछ लोगों को पैरालिसिस यानी लकवा भी हो सकता है।

कैसे फैलता है रेबीज

रेबीज लार से फैलने वाला रोग है। संक्रमित जानवर के लार का संपर्क जब व्यक्ति के खून से होता है, तो ये वायरस फैलता है। व्यक्ति के खून में ये वायरस या तो जानवर के काटने से पहुंचते हैं या पालतू जानवरों के घाव और चोट आदि के चाटने से फैलते हैं। अगर व्यक्ति की त्वचा कहीं भी कटी–फटी नहीं है, तो इस वायरस के फैलने का खतरा नहीं होता है।

क्या हैं रेबीज के लक्षण

रेबीज से ग्रसित व्यक्ति में रेबीज के लक्षण बहुत दिनों के बाद उभरते हैं, रेबीज के आम लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं:

बुखार, सिरदर्द , घबराहट या बेचैनी, चिंता और व्याकुलता,भ्रम की स्थिति

खाना–पीना निगलने में कठिनाई, बहुत अधिक लार निकलना, पानी से डर लगना (हाईड्रोफोबिया), पागलपन के लक्षण, अनिद्रा, एक अंग में पैरालिसिस यानी लकवा मार जाना,

सालों बाद भी दिख सकते हैं रेबीज के लक्षण

रेबीज से संक्रमित होने के एक सप्ताह के बाद या कई सालों बाद लक्षण उभर सकते हैं। ज्यादातर लोगों में रेबीज के लक्षण चार से आठ सप्ताह में विकसित होने लगते हैं। अगर रेबीज से संक्रमित जानवर किसी की गर्दन या सिर के आस–पास काट लेता है तो लक्षण तेजी से उभरते हैं क्योंकि तब ये वायरस व्यक्ति के दिमाग तक जल्दी पहुंच जाते हैं। रेबीज के प्रारंभिक लक्षणों में आमतौर पीड़ित व्यक्ति को उस जगह पर झुनझुनी होती है, जिस जगह जानवर ने उसे काटा है। इसके अलावा बुखार, भूख न लगना और सिरदर्द जैसी शिकायत भी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जानवर ने काटा है, तो उसे जल्द से जल्द चिकित्सक से मिलना चाहिए और एंटीरेबीज टीके लगवाने चाहिए।

क्या करें अगर जानवर काट ले

जानवरों के काटने पर काटे गए स्थान को तुरंत पानी व साबुन से अच्छी तरह धो देना चाहिए। धोने के बाद काटे गए स्थान पर अच्छी तरह से टिंचर या पोवोडीन आयोडिन लगाना चाहिए। ऐसा करने से कुत्ते या अन्य जानवरों की लार में पाए जाने वाले कीटाणु सिरोटाइपवन लायसावायरस की ग्यालकोप्रोटिन की परतें घुल जाती हैं। इससे रोग की मार एक बड़े हद तक कम हो जाती है, जो रोगी के बचाव में सहायक होती है। जानवर के काटने के तुरंत बाद रोगी को टिटेनस का इन्जेक्शन लगवाना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह से काटे गए स्थान का उचित इलाज करना चाहिए।

क्या कहती हैं हैड आशा वर्कर अनु कौशल

हैड आशा वर्कर चंबा अनु कौशल का कहना है कि अक्तूबर में जब गाय की मौत के बात रेबीज का खतरा गांव में पैदा हुआ तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में मिशन रीव ने पूरा सहयोग दिया और उन लोगों को भी जागरूक किया जो दूरदराज के क्षेत्र में रहते हैं। इस दौरान मिशन रीव जिला संयोजक और उनकी टीम में विकास शर्मा और मीनाक्षी ने गांव के उन लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया।

क्या कहते हैं पंचायत प्रधान किशन चंद

थला में रेबीज के खतरे से निपटने के लिए मिशन रीव ने सराहनीय योगदान दिया। गांव के लोगों को उनके घर जाकर समय रहते जागरूक करना अपने आप मे बड़ी उपलब्धि है। अभी तक इस गांव में रेबीज का कोई मामला उस घटना से संबंधित सामने नहीं आया है।

क्या कहते हैं मिशन रीव जिला समन्वयक राकेश शर्मा

थला में अक्तूबर में रेबीज के संभावित खतरे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया था। उस दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों से भी बात की गई थी। तब बताया गया था की कुछ मामलों में रेबीज के लक्षण दो–तीन माह बाद भी दिखते हैं। इसी के चलते मिशन रीव की टीम ने दोबारा उन गांवों का दौरा किया। यह खुशी की बात है कि उस दौरान लोगों ने मिशन रीव के जागरूकता अभियान से जागरूक होकर टीकाकरण करवाया और गांव के लोगों के मुताबिक तीन माह बाद सभी स्वस्थ्य है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गयी एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिया जाता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केन्द्र की भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं के नाम पर दिया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत भारत सरकार वर्ष 2020 तक देश में 8 करोड़ से अधिक BPL और गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2018–19) तक देश भर में 5.5 करोड़ BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देशय

उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना के लागू करने का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी सुरक्षा की जा सकती है।

वर्तमान में उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।

माना जा रहा है कि जो बीमारियाँ खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने से होती हैं, उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद उनमें भी कमी हुई है। इस प्रकार यह योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रखने में भी सहायक साबित हो रही हैं।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कैसे आवेदन करें

योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी LPG वितरण केंद्र में जमा कराना है।

उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र LPG वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। 2 पन्ने के आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जन धन / बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है।

आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदक यह चयन कर सकता है कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला।

आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Download Application Form for PM Ujjwala Yojana

योजना के मुख्य बिंदु

योजना का नाम	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
शुभारंभ	1 मई 2016
मंत्रालय	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मुख्य उद्देश्य	गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना
वित्तीय सहायता	प्रत्येक BPL परिवार को 1600 रुपये की सहायता
पात्रता	SECC – 2011 डेटा

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ ही जमा करानी होगी। जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है।

- पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL प्रमाणपत्र
- BPL राशन कार्ड
- एक फोटो ID जैसे कि आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस
- लीज करार
- टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल
- पासपोर्ट की प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व–घोषणा प्त्र
- राशन कार्ड फ्लैट आवंटन / कब्ज़ा प्त्र
- LIC पालिसी
- बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट

- दिए गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी LPG वितरण केंद्र से ही संपर्क करें।

उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए इच्छुक लोगों का योजना के लिए पात्र होना अति आवश्यक है। जो भी आवेदक पात्र नहीं पाये गए उन्हें गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। पात्रता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।

आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी को SECC – 2011 डेटा के साथ मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात ही यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक योजना का पात्र है या नहीं। आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।

आवेदक BPL परिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिला ही होनी चाहिए, पुरुष इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से ही कोई भी LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आवेदक के पास BPL प्रमाण पत्र अथवा BPL राशन कार्ड का होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी ठीक होनी चाहिए।

योजना के लिए पात्र BPL परिवारों की सूची राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से तैयार की जाती है। तेल व्यापार कम्पनियां इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी ग्रामीण आवेदकों की जानकारी को SECC – 2011 के डेटाबेस के साथ मैच करती है और उसके बाद ही गैस कनेक्शन जारी होता है।

योजना का बजट और वित्त पोषण

योजना का वित्त पोषण अथवा योजना पर खर्च होने वाला पैसा LPG सब्सिडी में बचाए गए पैसे से होगा। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 में शुरू किये गए "गिव–इट–अप" अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 1.13 करोड़ से अधिक लोगों ने LPG सब्सिडी छोड़ दी है और वो लोग बाजार मूल्य पर LPG सिलिंडर खरीद रहे हैं। चलाये गए अभियान से अभी तक हज़ारों करोड़ रुपये कि बचत हो चुकी है जिसे उज्ज्वला योजना के लिए इस्तेमाल करने का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता

योजना के अंतर्गत भारत सरकार प्रत्येक पात्र BPL परिवार को 1600 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो कि गैस कनेक्शन खरीदने के लिए है।

भारत सरकार BPL परिवारों को स्टोव खरीदने और पहली बार सिलिंडर भरवाने के लिए आने वाले खर्च को अदा करने के लिए किस्तों की सुविधा भी प्रदान करती है।

योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की इस तरह की ये पहली योजना है जिससे करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को लाभ हो रहा है।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

उज्ज्वला योजना के दिशा निर्देश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने योजना के दिशा निर्देश भी प्रकाशित कर दिए हैं। दिशा निर्देश पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड करें।

http://www-petroleum-nic-in/docs/UJJWALA-pdf

क्या क्या मिलेगा

एक नया खाली LPG सिलिंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर, मुफ्त DGCC पुस्तिका, एक सुरक्षा नली, मुफ्त इंस्टालेशन

अन्य उद्देश्य

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बच्चों और महिलाओं में अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोगों में कमी लाना, भीतरी और बाहरी वायु प्रदूषण को कम करना।

लक्ष्य – 2020 तक 8 करोड़ से अधिक BPL परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित करना।

हिमाचल में उज्वला योजना

2019 तक सभी पात्र होंगे लाभान्वित

अभी तक 73074 एलपीजी कनेक्शन बांटे

अगस्त में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को 73074 एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इनके अलावा अन्य सभी पात्र व्यक्तियों को 2019 से पूर्व कनेक्शन प्रदान किए हैं।

वर्ष 2018 के टॉप– घटनाक्रम एक नज़र में

भारत का पहला सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर 'प्रत्यूष' लॉन्च

केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 08 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टीपेटाफ्लोप्स सुपर कम्प्यूटर देश को समर्पित किया। इस सुपर कम्प्यूटर को सूर्य के नाम पर प्रत्यूष नाम दिया गया है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में और सुधार होगा।

ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का 43वां सदस्य बना भारत

भारत द्वारा 19 जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) का सदस्य बनना एक महत्वपूर्ण कामयाबी रही। इस समूह की सदस्यता के मिलने पर भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए मजबूती से दावेदारी रख सकता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) परमाणु अप्रसार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यातों से रासायनिक या जैविक हथियारों का विकास नहीं हो सके।

पहली बार सौरमंडल के बाहर किसी चंद्रमा का साक्ष्य मिला

खगोल वैज्ञानिकों ने हब्बल एवं केपलर अंतरिक्ष दूरबीनों की मदद से हमारे सौरमंडल के बाहर पहले चंद्रमा (एक्जोमून) का पता लगाया है। यह धरती से 8,000 प्रकाश वर्ष दूर एक विशालकाय गैसीय ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। ऐसा पहली बार है जब सौरमंडल के बाहर किसी चंद्रमा की खोज गई है। 'साइंस एडवांसेस' पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार यह एक्जोमून अपने बड़े आकार (नेपचून के व्यास की तुलना में) के कारण अनोखा है।

पनडुब्बी 'करंज' भारतीय नौसेना में शामिल

मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) से स्कॉर्पीन क्लास की तीसरी पनडुब्बी 'करंज' 31 जनवरी 2018 को लॉन्च की गयी। करंज को प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के तहत एमडीएल द्वारा बनाया गया है। यह इस परियोजना के तहत बनाई जाने वाली छह पनडुब्बियों में से तीसरी है।

स्वदेश निर्मित ड्रोन रुस्तम–2 का सफल परीक्षण

भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) ने 25 फरवरी 2018 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित अपने परीक्षण केंद्र से स्वदेश निर्मित ड्रोन रुस्तम–2 का सफल परीक्षण किया। इस ड्रोन को भारत में ही बनाया गया है। डीआरडीओ की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि मध्यम ऊंचाई तक और लंबी अवधि तक उड़ने वाले इस ड्रोन का विकास सेना की तीनों शाखाओं के लिए किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 विस्तृत समीक्षा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 29 जनवरी 2018 को आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान जीडीपी के 7 से 7.5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं तेजी से महंगा होता क्रूड भी सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक है जिसके इस वर्ष 12 प्रतिशत और महंगा होने का अनुमान है। वर्ष 2016–17 में जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत दर्ज करने के बाद 2017–18 में जीडीपी वृद्धि दर 7 से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। इस कमी के बावजूद भारत की जीडीपी 2014–15 से 2017–18 तक औसतन 7.3 प्रतिशत रही जो कि विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी बेहतर है।

कुसुम योजना: 3 करोड़ सिंचाई पंप सौर उर्जा से लैस होंगे

आम बजट 2018–19 के दौरान की गई विभिन्न घोषणाओं में देश की सिंचाई व्यवस्था के लिए कुसुम योजना की घोषणा की गई। यह योजना देश के किसानों एवं कृषि व्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से राष्ट्रीय पोषण मिशन आरंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 08 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझूनू जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत सभी बच्चों को उचित पोषण मिलना सुनिश्चित किया जायेगां राष्ट्रीय पोषण मिशन एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन करेगा।

- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'लक्ष्य' कार्यक्रम की घोषणा की**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मार्च 2018 को प्रसूति गृह और ऑपरेशन कक्ष में देखभाल में गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से हाल ही में 'लक्ष्य' कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम से प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू), उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार होगा।

RUSA योजना को 2020 तक जारी रखने की मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए निधि आवंटित करती है। रूसा के तहत सरकार का लक्ष्य 2020 तक कुल नामांकन अनुपात 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना है।

आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने यह योजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लॉन्च की। इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों और 50 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यहां पर पहले चरण की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई है। योजना आरंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश में 1.5 लाख गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलेंगे। यहां केवल बीमारी का इलाज ही नहीं होगा बल्कि स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिलेगी।

महिला फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने रचा इतिहास, अकेले उड़ाया मिग–21 विमान

भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले मिग–21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा। अवनी चतुर्वेदी ने गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरकर अपना मिशन पूरा किया। वह अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली वह भारत की पहली महिला बन गई हैं। अवनी के इस मिशन से पहले ही पूरी तरह मिग–21 बाइसन एयरक्राफ्ट की जांच की। अवनी के मिग में सवार होने पर अनुभवी फ्लायर्स और प्रशिक्षकों ने जामनगर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रन–वे पर लगातार नज़र बनाये रखी।

स्टीफन हॉकिंग का निधन, जानिए उनका जीवन एवं वैज्ञानिक सिद्धांत

विश्व के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक एवं ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताने वाले महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। स्टीफन हॉकिंग के परिवार ने 13 मार्च 2018 को एक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की है। हॉकिंग के परिवार में उनके बच्चे लूसी, रॉबर्ट और टिम हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के बहुत से अहम् रहस्यों के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी जो विश्व भर में विशिष्ट स्थान रखती है। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया है। उनके पास 12 मानद डिग्रियां थीं। स्टीफन हॉकिंग के कार्यों के चलते उन्हें अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है।

नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लियोन लीडरमैन का निधन

गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकविद लियोन लीडरमैन का अमेरिका के रेक्सबर्ग शहर में 03 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। लियोन लीडरमैन का जन्म 15 जुलाई 1922 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। लीडरमैन को वर्ष 1988 में अधिक ऊर्जा वाले एक्सेलेरेटर की मदद से न्यूट्रिनॉज़ की बीम बनाने और न्यूट्रिनो के नए प्रकार 'म्यूऑन न्यूट्रिनो' के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल मिला था। लीयोन लीडरमैन अमेरिका के प्रसिद्द वैज्ञानिक थे।

देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन

आजादी के बाद देश की पहली आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का 17 सितम्बर 2018 को मुंबई के अंधेरी स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थीं। अन्ना राजम मल्होत्रा ने देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई और देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्हें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) का कार्य मिला था। अन्ना राजम मल्होत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

आंग सान सू की को दिया गया मानवाधिकार सम्मान वापिस लिया गया

अमेरिका स्थित हॉलोकास्ट म्यूज़ियम ने 08 मार्च 2018 को म्यांमार की नेता आंग सान सू की को दिए गये प्रतिष्ठित मानवाधिकार सम्मान को वापिस लेने की घोषणा की है। हॉलोकास्ट म्यूज़ियम का आरोप है कि सू की रोहिंग्या मुस्लिमों पर हो रहे हमलों को रोकने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही हैं।

अनुकृति वास ने जीता मिस इंडिया 2018 का खिताब

तमिलनाडु की अनुकृति वास ने 19 जून 2018 को 'फेमिना मिस इंडिया 2018' का खिताब जीता। अनुकृति वास ने 29 प्रतियोगियों को हरा कर इस खिताब को जीता। इस प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अनुकृति वास को ताज पहनाया। अनुकृति वास इससे पहले मिस तमिलनाडू 2018 का खिताब जीता था। मुंबई में आयोजित हुए इस कॉन्टेस्ट में हरियाणा की रहने वाली मीनाक्षी चौधरी फर्स्ट रनर–अप बनीं और सेकेंड रनर–अप आंध्र प्रदेश की रहने वाली श्रेया राव बनीं। वहीं दिल्ली की रहने वाली गायत्री भारद्वाज, झारखंड की रहने वाली स्टेफी पटेल टॉप 5 में शामिल थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल शांति पुरस्कार – 2018' के लिए चयनित

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2018 के 'सियोल शांति पुरस्कार' के लिए चयनित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए दिया जायेगा। पुरस्कार समिति ने भारत में अमीर और गरीब के बीच के सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करने के लिए उनकी 'मोदीनॉमिक्स' को सराहा है। सियोल शांति पुरस्कार सांस्कृतिक फाउंडेशन के चेयरमैन क्वॉन ई–हायोक की अध्यक्षता में सियोल के जंग–यू में हुई चयन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।

मिस यूनिवर्स 2018: फिलीपींस की कैटरिओना ग्रे ने जीता ख़िताब

फिलीपीन्स की 24 वर्षीय कैटरिओना इलिसा ग्रे (Catriona Elisa Gray) मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई हैं। इस खिताब को हासिल करने वालीं वह चौथी फिलीपीनी महिला हैं। बैंकॉक (थाईलैंड) में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में कैटरिओना ग्रे ने 93 प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए यह खिताब हासिल किया।

मेघालय में दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा 'क्रेम पुरी' की खोज की गयी

मेघालय में 'क्रेम पुरी' नामक 24,583 मीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा की खोज की गयी है। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में दुनिया की सबसे बड़ी बलुआ पत्थर की गुफा है। यह भूमिगत गुफा, ईदो जूलिया, वेनेजुएला की विश्व रिकॉर्ड धारक 'क्यूवा डेल समन' नामक गुफा से 6,000 मीटर से अधिक लंबी है।

इसरो ने GSAT-6A सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 29 मार्च 2018 को GSAT-6A सैटेलाइट लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट अगले 10 वर्ष तक काम करेगा। इसे जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी–एफ08) से भेजा गया।

इसरो ने IRNSS-1I नैविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 12 अप्रैल 2018 को अपने अंतरिक्ष केन्द्र से पीएसएलवी–सी41 प्रक्षेपण यान द्वारा आईआरएनएसएस–1आई उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया। इस प्रक्षेपण से 32 घंटे पूर्व उलटी गिनती आरंभ की गई थी जिसके बाद तड़के करीब चार बजकर चार मिनट पर पीएसएलवी–सी41 प्रक्षेपण यान आईआरएनएसएस–1आई उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष के लिये रवाना हुआ और कुछ देर बाद उपग्रह को उसकी पूर्वनिर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया।

तेजस लड़ाकू विमान ने 'डेक लैंडिंग' परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया

स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस के नौसेना प्रोटोटाइप ने 02 अगस्त 2018 को विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर 'डेक लैंडिंग' परीक्षण के दौरान डेक से संपर्क बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की. इसके साथ ही भारत लड़ाकू विमानों की डेक लैंडिंग कराने वाले अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया।

नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन लॉन्च किया

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की संरचना को गहराई से समझने के अपने महत्वपूर्ण मिशन के तहत एक और सफल कदम बढ़ाते हुए दो मिनी सेटेलाइटों के साथ 'इनसाइट' यान का प्रक्षेपण किया. यह यान इस वर्ष नवंबर में मंगल की सतह पर उतरेगा। एटलस–पांच रॉकेट के माध्यम से इस यान का कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग एयर फोर्स स्टेशन से सफल प्रक्षेपण किया गया। नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिडेंस्टाइन ने वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी तथा बयान जारी किया कि इस यान के प्रक्षेपण से मंगल के बारे में नयी और सटीक जानकारियां मिलेंगी।

बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना

राजस्थान भारत सरकार की राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति (जैव ईंधन नीति) 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण उच्चाधिकार समिति की चतुर्थ बैठक में बायोफ्यूल नीति 2018 को प्रदेश में लागू करने को अनुमोदन किया।

परमाणु पनडुब्बी अरिहंत ने पहला गश्ती अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया

भारत की सामरिक परमाणु पनडुब्बी अर्थात् न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने 05 नवंबर 2018 को अपना पहला गश्ती अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के अधिकारियों और कर्मियों से मुलाकात की।पनडुब्बी अरिहंत के इस अभ्यास से भारत के नाभिकीय त्रिकोण की पूर्ण स्थापना हुई।

जापान ने दक्षिण चीन सागर में पहली बार पनडुब्बी अभ्यास किया

जापान ने पहली बार विवादित दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी अभ्यास किया है। यह सैन्य अभ्यास हालांकि चीन के दावे वाले जलक्षेत्र से दूर किया गया. मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की पनडुब्बी कुरोशियो ने अन्य जंगी जहाजों के साथ दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया।

900 वर्ष तक सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई: आईआईटी खड़गपुर

आईआईटी, खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा किये गये अध्ययन में यह पाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत सैंकड़ों वर्षों के भयंकर सूखे के कारण हुआ। शोधकर्ताओं ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों को एक शोध में पता चला है कि यह सूखा कुछ साल या कुछ दशक नहीं बल्कि पूरे 900 साल तक चला था।

छह वर्षों में भारत में कैंसर के मामलों में 15.7 प्रतिशत वृद्धि: अध्ययन

ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी (ग्लोबोकेन) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले छह वर्षों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़े वर्ष 2012 से 2018 तक के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में लगभग 11.57 लाख कैंसर के मामलें दर्ज किये गए, जो कि वर्ष 2012 में दर्ज 10 लाख मामलों की तुलना में 15.7 प्रतिशत अधिक हैं।

भारत और अमेरिका के बीच पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन

भारत और अमेरिका ने 06 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली में पहली बार टू प्लस टू (2+2) वार्ता का आयोजन किया. टू प्लस टू बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अमेरिका की अफगान नीति का समर्थन करता है। इसके बाद सुषमा स्वराज ने भारत और अमेरिका की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में मीडिया को संबोधित किया।

गंगा विश्व की सबसे संकटग्रस्त नदियों में से एक: डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रिपोर्ट

वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग सभी दूसरी भारतीय नदियों की तरह गंगा में लगातार पहले बाढ़ और फिर सूखे की स्थिति पैदा हो रही है

भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत 80वें स्थान पर: विश्व बैंक रिपोर्ट

विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली वितरण में पिछले कुछ साल से उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत अभी भी विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा भरोसेमंद आपूर्ति अभी भी कम है।

विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस में नहीं बिकेगा जंक फूड: यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किया है। यह पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक निर्देश के बाद जारी किया गया है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 समापन : भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर

गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) में हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का 15 अप्रैल 2018 को समापन हो गया, जिसमें कुल 66 पदक जीतने वाला भारत 26 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 80 स्वर्ण समेत 198 पदक जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया पदकतालिका में पहले स्थान पर और 45 स्वर्ण समेत 136 पदक जीतने वाला इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा। भारत वर्ष 2010 में दूसरे स्थान पर था। भारत की दिग्गज मुक्केबाज एम सी मेरीकॉम राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रहीं। बर्मिंघम में वर्ष 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जायेगा।

विश्व में तीन करोड़ बच्चे मौत के कगार पर: यूनिसेफ रिपोर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) सहित वैश्विक गठबंधन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार समयपूर्व पैदा हुए लगभग तीन करोड़ बच्चे मौत की कगार पर हैं। इन बच्चों को जीवित रखने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट 'जीवित रहें और बढ़ें: हर छोटे एवं बीमार नवजात शिशु देखभाल में सुधार' नाम से प्रकाशित की गई है। समय से पूर्व पैदा होने वाले बच्चों में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इनमें ज्यादातर समस्याएं प्रसव के दौरान बच्चों की देखभाल करने की होती हैं।

असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अंतिम मसौदा जारी

असम सरकार द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स – एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदा को जारी कर दिया गया है। इसे इसलिए जारी किया गया है ताकि असम में अवैध तौर पर रह रहे लोगों का पता लगाया जा सके। केंद्र सरकार ने भी असम और आसपास के राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां भेजी हैं। सीमाओं पर केंद्रीय बलों के अलावा इंडियन रिज़र्व बटालियन (आईआरबी) की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत 57वें स्थान पर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) की सूची में भारत 57वें नंबर पर है, पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था। चीन विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। यह सालाना रैंकिंग कॉर्नेल विश्वविद्यालय, आईएनएसईएडी और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा 10 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई। स्विटजरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। जबकि दुनिया भर की रैंकिंग में भारत 57वें स्थान पर है।

आंचल ठाकुर स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय

आंचल ठाकुर स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कीइंग में भारत का यह पहला पदक है। आंचल ठाकुर ने तुर्की में हुई एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। आंचल ठाकुर ने 'अल्पाइन एडर–3200 कप' टूर्नामेंट में यह पदक अपने नाम किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 से बीएस–4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को निर्देश जारी करते हुए कहा कि देशभर में 01 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज–4 (बीएस–4) श्रेणी के वाहन नहीं बेचे जाएंगे न ही इनका पंजीकरण होगा। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वे मानक हैं जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषक तत्वों के नियमन के लिए बनाए हैं। भारत स्टेज–6 (या बीएस–6) उत्सर्जन नियम एक अप्रैल, 2020 से देशभर में प्रभावी हो जाएंगे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी

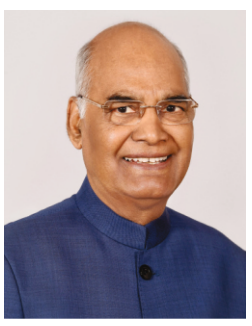

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 19 सितंबर 2018 को ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति के पास भेजा था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ट्रिपल तलाक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। सरकार के पास अब बिल को शीत सत्र तक पास कराने का वक्त है। तीन तलाक देना अब अपराध है. बता दें कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ दल इस विधेयक के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग करते रहे हैं।

स्त्रोत : जागरण जोश ऑन लाइन

Advertorial

अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते है: तो उठाएं इस अवसर का लाभ

प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित

ऑन लाईन आवेदन ही होंगे स्वीकार

अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पुराने व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के इच्छुक हैं तो मिशन रीव आपके इस सपने को साकार करने में पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। रीव न केवल व्यवसाय को शुरू करने में आपकी मदद करेगा बल्कि एक सारथी की तरह उस व्यवसाय को आगे ले जाने में आपकी पूरी मदद करेगा। इतना ही नहीं व्यवसाय को शुरू करने से लेकर अगले एक साल तक उस व्यवसाय के पूरी तरह स्थापित होने तक मिशन रीव हर पल आपके साथ रहेगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को मिशन रीव के पास ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और मिशन के साथ जुड़ना होगा।

मिशन रीव आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव उद्यमिता विकास कार्यक्रम (इडीपी) के तहत लघु/कुटिर उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। इस कार्यक्रम के तहत आवेदक को पंजीकरण, अन्नापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, प्रशिक्षण तथा व्यवसाय/उद्योग स्थापित करने आदि में संपूर्ण सहयोग दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण आवेदक को संबंधित जिला या आईआईआडी मुख्यालय में दिया जाएगा।

आप कैसे इस योजना का लाभ लेकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं इसकी प्रक्रिया आप निम्नलिखित विविरण से समझ सकते हैं।

उद्देश्य

- अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को मार्गदर्शन करना
- नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना
- वांछित व्यवसाय शुरू करने के लिए उनकी क्षमता और कौशल का आकलन करना
- कम जोखिम में अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में सहयोग देना
- उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना
- सर्वांगीण विकास में सहयोग करना
- भविष्य के लिए बेहतर योजना तैयार करने में सहयोग करना

ऐसे काम करेगा मिशन

अगर आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो मिशन रीव उसमें एक सहयोगी के तौर पर आपका सहयोग करेगा। यहां पर बंद हो चुके व्यवसाय को पुनः शुरू करने का विकल्प भी मिशन रीव दे रहा है। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो व्यवसाय शुरू करने से लेकर एक साल तक व्यवसाय स्थापित करने तक मिशन रीव आपके साथ रहेगा और आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में पूरा सहयोग करेगा।

इसके लिए जो भी दस्तावेजी औपचारिकताएं जैसे कि अन्नापति प्रमाण पत्र लेना, विभागीय अनुमति लेना, व्यवसाय शुरू करने से संबंधित योजनाओं की जानकारी, लोन का प्रबंध व अन्य दस्तावेजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने में मिशन रीव व्यवसायी की पूरी मदद करेगा।

मिशन रीव का फोकस

- प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम एवं गुणवत्तापरक पठन सामग्री का खाका तैयार करना
- बेहतरीन प्रश्नावली तैयार कर भावी उद्यमियों से व्यवसाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना
- लघु अवधि प्रशिक्षण के लिए संभावित उद्यमियों का चयन करना
- उद्यमशील योग्यताओं की क्षमता की पहचान करना
- प्रबंधकीय समझ और आधारभूत कौशल विकास, विश्लेषणात्मक मानव प्रशासकीय और तकनीकी कौशल प्रदान करना
- उद्यमियों को उनकी क्षमता के अनुसार बेहतर व्यवसाय का चयन करने में मदद और औद्योगिक प्रोजेक्ट दिलाने में मदद करना

कैसे करें आवेदन

मिशन रीव के तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए मिशन रीव की ओर से ऑनलाइन पोर्टल पर लिंक http://edp.missionriev.in उपलब्ध है। इस लिंक में दिशानिर्देशों के मुताबिक कोई भी अपना पंजीकरण करवा सकेगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने स्कीम एप्लीकेशन खुलेगी। इसमें जैसे ही आप Select Scheme पर click करेगें वैसे ही योजना का पूरा विवरण और इसके लिए योग्यता आदि जानकारी आपके सामने आ जाएगी । आप अपनी इच्छा अनुसार उस योजना को चयनित कर सकते है जिसमें आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है। इसके बाद निर्देशानुसार आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पूरी जानकारी भरने के बाद अन्त में रजिस्टर बटन पर click करना होगा। पंजीकरण होने के एक सप्ताह के भीतर आपको आपके द्वारा दिए हुए दूरभाष नं. अथवा ईमेल आईडी पर प्रशिक्षण की तिथी और स्थान के बारे में जानकारी दे दी जाएगी।

ये रहेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

पहला चरण

- ऑनलाइन पंजीकरण
- विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कांउसलिंग

दूसरा चरण

- 6 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम
- ईडीपी का कान्सेप्ट फ्रेमवर्क
- प्रक्रिया और चुनौतियां
- वांछित विशेषताएं
- व्यवसाय योजनाओं की पहचान
- प्रत्येक उद्यमी के साथ बिजनेस आइडिया मैपिंग
- व्यवसाय योजना की रूपरेखा तैयार करना और नई योजना बनाना

तीसरा चरण

- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना
- कंपनी, साझेदार फर्म अथवा व्यवसायी के तौर पर पंजीकरण
- जिला उद्योग केंद्र के साथ पंजीकरण
- संबंधित एजेंसी को वांछित दस्तावेजों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना
- पैन/आधार/ जीएसटी आदि तैयार करना
- उद्यम के अनुसार अन्नापति प्रमाण

चौथा चरण

- व्यवसाय के लिए सहयोग
- प्रारंभिक एक माह में पूर्ण सहयोग?

पांचवा चरण

अगने 11 महीनें तक मार्गदर्शक के तौर पर न्यूनतम शुल्क के साथ सहयोग।

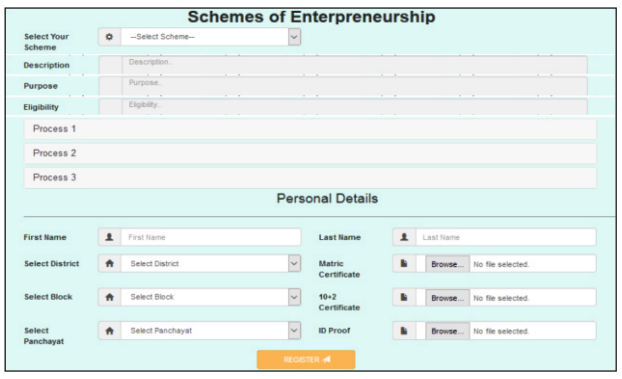

नियम व शर्तें

व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए देय निर्धारित शुल्क आवेदन करने वाले व्यक्ति को कंपनी के नियम और शर्तों के अनुसार अदा करना होगा। शुल्क योजना के अनुसार लिया जाएगा जिसकी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही पोर्टल पर दिए गए दिशानिर्देशों को भी अच्छी तरह समझना और उनका अनुसरण करना अनिवार्य रहेगा।

आयु : प्रार्थी (अनु0जाति,अनु.जन0,सामान्य वर्ग) की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए जबकि महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट रहेगी ।

उद्यम का प्रकार :
विनिर्माण (मैन्युफेक्चरिंग) / सेवा /व्यवसाय

ऋण के प्रकार :
10,000/रुपये से 1 करोड़ रुपये तक या प्रोजेक्ट के अनुसार।

व्यवसाय के प्रकार :
विनिर्माण(मैन्युफेक्चरिंग)/सेवा /व्यवसाय के लिए जो क्रेडिट(सॉफ्ट लोन एवं कार्यशील पूंजी) लोन सुविधा है उसके लिए किसी भी प्रकार की कोलेटरल सेक्युरिटी/तृतीय पक्ष गारंटी नए व्यवसाय और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु मान्य नहीं है ।
योजनानुसार कोलेटरल सेक्युरिटी लोन
पुनःभुगतान सूची/कार्यक्रम : 3 से 7 वर्ष

आकर्षक ब्याज योजना :
शेष राशि पर ही ब्याज अदायगी

साधारण सेवा शुल्क :
कुल परियोजना लागत का मात्र 3 प्रतिशत
पारदर्शी प्रलेखन :
अवधि ऋण, कार्यशील ऋण तथा नकद ऋण :
प्रमोटर का मार्जिन : अधिकतम 25 प्रतिशत

आईआईआरडी की सेवाएं

दस्तावेज़ों की सूची :

लोन लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ : आवश्यकता आधारित

परामर्श सहयोग

व्यापार वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यापार वृद्धि में सहयोग

उचित उत्पाद का विज्ञापन एवं विस्तार सहयोग

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति संस्थान के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवदेन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पोर्टल खुल चुका है । आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे।

यहां करें आवेदन http://edp.missionriev.in अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- 93185-16777

0177– 2640761, 2844073 pravin.riev@iirdshimla.org info@iirdshimla.org